वर्ष 13 • अंक 9 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

बुधवार 26 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

सोना गिरा, लेकिन दूर रहे खरीदार

बिन्नी बंसल पृष्ठ 3

बिन्नी बंसल का फिनटेक लेनदार 'रुपीक' पर दांव

डॉलर रु. 71.90 ▼ 10 पैसे | यूरो रु. 77.90 (अपरिवर्तित) | सोना (10ग्राम) रु 42637 ▼ 778 रुपये | सेंसेक्स 40281.20 ▼ 82.00 | निफ्टी 11797.90 ▼ 31.50 | निफ्टी फ्यूचर्स 11823.20 ▲ 25.30 | ब्रेंट क्रूड 55.50 डॉलर ▼ 02.10 डॉलर

एक नज़र

एसबीआई कार्ड्स का मूल्य दायरा 750-755 रुपये

भारतीय स्टेट बैंक की सहायक इकाई एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट्स सर्विसेज ने आईपीओ निर्गम का मूल्य दायरा 750 से 755 रुपये प्रति शेयर तय किया है। निर्गम का आकार 10,355 करोड़ रुपये होगा। आईपीओ के जरिये एसबीआई इस कंपनी में अपनी 4 फीसदी और कार्लाइल 11 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। एसबीआई कार्ड्स घरेलू बाजार में सूचीबद्ध होने वाली पहली क्रेडिट कार्ड कंपनी होगी। पृष्ठ 3

सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों को एच1एन1 संक्रमण

उच्चतम न्यायालय के 6 न्यायाधीशों में एच1एन1 संक्रमण के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने मंगलवार को न्यायाधीशों के साथ बैठक की और इस संक्रमण से बचने के लिए सभी वकीलों तथा न्यायालय के कर्मचारियों के टीकाकरण का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड ने अपने कोर्ट रूम में वकीलों को यह जानकारी दी।

बतानी होगी खुली मिठाई की एक्पायरी डेट

सरकार स्थानीय दुकानों पर मिलने वाले खाने-पीने के सामान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही है। इसके तहत जून 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि प्रदर्शित करनी होगी। अभी डिब्बाबंद मिठाई पर ही यह जानकारी देना अनिवार्य है।

बढ़ सकती है एयर इंडिया के लिए बोली की समय सीमा

एयर इंडिया के लिए बोली सौंपे जाने की आखिरी तारीख को 17 मार्च से आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। गृह मंत्री की अध्यक्षता वाला अंतरमंत्रालयी समूह नई तारीख पर इस सप्ताह निर्णय कर सकता है। सरकार ने घाटे में चल रही एयर इंडिया में अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए 27 जनवरी को आरंभिक सूचना ज्ञापन जारी किया था।

दिल्ली हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 11 व्यक्तियों की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप रंधावा ने कहा कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्से अभी भी हिंसा की चपेट में हैं। रंधावा ने कहा कि हिंसा के संबंध में 11 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पृष्ठ 11

डॉनल्ड ट्रंप की यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच और प्रगाढ़ होंगे संबंध

व्यापार पर नहीं बनी बात

अर्चिस मोहन, शुभायन चक्रवर्ती और श्रेया जय
नई दिल्ली, 25 फरवरी

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की 36 घंटे की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर कोई प्रगति नहीं हुई और गतिरोध अपनी जगह बरकरार रहा। ट्रंप ने कश्मीर पर अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया और इस मुद्दे पर भारत तथा कश्मीर के बीच मध्यस्थता की पेशकश को एक बार फिर दोहराया। साथ ही उन्होंने भारत में धार्मिक सहिष्णुता के मुद्दे का भी जिक्र किया।

दोनों पक्ष ट्रंप के इस दौरे से संतुष्ट नजर आए। भारत ने इसे असाधारण दौरा बताया। उसका कहना था कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। ट्रंप के इस दौरे से अमेरिका में भारत के प्रति काफी दिलचस्पी देखने को मिली।

यह दौरा मोदी के लिए भी व्यक्तिगत जीत थी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें सख्त और सक्षम नेता बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की। लेकिन दोबारा राष्ट्रपति चुनावों की तैयारी कर रहे ट्रंप के लिए भी यह दौरा व्यक्तिगत मोर्चे पर सफल रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप मंगलवार को नई दिल्ली में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में। *फोटोः संजय शर्मा*

संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों पक्षों ने 3 अरब डॉलर के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अमेरिका से अपाचे और एचएच-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदेगा। शाम को एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने भारत के साथ 16.9 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को पाटने की उम्मीद जताई और अमेरिका में भारतीय कारोबारियों द्वारा किए गए निवेश की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति खासकर भारत में मिले सम्मान से बेहद गदगद नजर आए।

संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को समग्र वैश्विक रणनीति साझेदारी के स्तर का बताया। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर चौतरफा पहल को नए सिरे से शुरू करने की इच्छा जताई। अभी तक भारत इस पहल पर सक्रियता नहीं दिखा रहा है क्योंकि वह चीन को अलग-थलग करने के पक्ष में नहीं है।

दोपहर में कई प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने नियमन को सरल बनाने की मांग की, जिससे कारोबारी माहौल में सुधार हो सके। ट्रंप ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताया और दोबारा निर्वाचित होने पर उम्मीद जताई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी और बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि अधिग्रहण और कारोबारी सौदे आसान हुए हैं और मंजूरियों में तेजी आई है। इस पर ट्रंप ने कहा, 'मैं जब तक रहूंगा ऐसा होगा लेकिन मेरी जगह कोई और आया तो यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है। हमने भारी-भरकम कर कटौती की है और नियमन को आसान बनाया है।'

भारत के शुल्क घटाने पर ही होगा व्यापार करार: ट्रंप

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 25 फरवरी

- समग्र व्यापार करार के लिए अभी करना होगा लंबा इंतजार
- व्यक्तिगत दोस्ती से व्यापारिक रुख में नहीं होगा बदलाव
- व्यापार करार की समयसीमा के बारे में नहीं दी जानकारी

भारत में आयात शुल्क दुनिया भर की तुलना में काफी ज्यादा है और व्यापारिक करार के लिए इसमें सुधार किए जाने की जरूरत है। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कही। हालांकि उन्होंने कहा कि इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है लेकिन व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर कब होंगे, उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

भारत और विदेशी मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने मोदी की नीतियों का समर्थन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मोदी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के पैरोकार हैं और चाहते हैं कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता हो। हलांकि उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत दोस्ती से आर्थिक संबंधों में अमेरिका के रुख में बदलाव नहीं आएगा। भारतीय उद्योगपतियों द्वारा अमेरिका में निवेश करने की ट्रंप ने सराहना की। लेकिन यह भी कहा कि भारत में उच्च शुल्क दरों को कम किए जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि हार्ली डेविडसन भारत में महंगी इसलिए बिकती है क्योंकि इस पर काफी ज्यादा शुल्क वसूला जाता है। हालांकि पिछले साल सरकार ने इस पर लगने वाले शुल्क में थोड़ी कटौती की है। उन्होंने कहा कि किसी तरह के व्यापार करार के लिए सभी क्षेत्रों में शुल्क घटाने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर वे व्यापार करार चाहते हैं तो उन्हें शुल्क कम करना होगा। हमने हाल ही में चीन के साथ भी ऐसा ही किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ समग्र व्यापार समझौते के लिए पहले से कहीं ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। (शेष पृष्ठ 13 पर)

हवाई अड्डों का निजीकरण फिलहाल ठंडे बस्ते में

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 25 फरवरी

छह हवाई अड्डों के निजीकरण के प्रस्तावित चरण को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बोली लगाने के लिए किसी कंपनी के पास कितने हवाई अड्डे हो सकते हैं, उस सीमा को लेकर सहमति नहीं बनने की वजह से प्रस्तावित चरण को टाला गया है।

समझा जाता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने बोलीदाताओं को सभी हवाई अड्डों के लिए बोली लगाने के नियम बनाए हैं, वहीं वित्त मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय ने हवाई अड्डों की संख्या पर सीमा लगाने को लेकर पत्र लिखा है। 2018 में निजीकरण के दौरान जब बोली के नियमों को अंतिम रूप दिया गया था उस समय भी वित्त मंत्रालय बोली के लिए हवाई अड्डों की संख्या पर सीमा लगाने के पक्ष में था।

हालांकि सचिवों की समिति के सुझावों के बाद सरकार ने सभी छह हवाई अड्डों के लिए कंपनियों को बोली लगाने की अनुमति दे दी। इसमें गौतम अदाणी के नेतृत्व वाली अदाणी एंटरप्राइजेज सफल बोलीदाता बनकर सामने आई और सभी छह हवाई अड्डे - लखनऊ, अहदमदाबाद, जयपुर, मंगलूरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी अपने नाम कर लिए। (शेष पृष्ठ 2 पर)

- वित्त मंत्रालय एक बोलीदाता के लिए हवाई अड्डों की संख्या सीमित करने की कही बात
- विमानन मंत्रालय और एएआई सभी हवाई अड्डों के लिए बोली की अनुमति देने के पक्ष में

एटीएम से नहीं मिलेंगे दो हजार के नोट!

रघु मोहन
मुंबई, 25 फरवरी

- एटीएम में तकनीकी बदलाव की प्रक्रिया तेज
- 2,000 की जगह 500 रुपये के डाले जाएंगे नोट
- नोटबंदी के बाद की यह सबसे बड़ी कवायद
- 2,000 रुपये के नोट धीरे-धीरे लिए जा रहे हैं वापस

बैंकिंग प्रणाली से 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके लिए देश के 2.40 लाख ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) में आवश्यक बदलाव हो रहा है। इन एटीएम में 2,000 रुपये की जगह 500 रुपये के नोट डालने के लिए यह तकनीकी फेरबदल किया जा रहा है। एटीएम के चार खानों (कैसेट) में से तीन में 500 रुपये के नोट भरे जाएंगे और चौथे खाने में 100 और 200 रुपये के नोट होंगे। कई एटीएम में 2,000 रुपये के नोट वाले कैसेट पहले ही बदले जा चुके हैं। बैंक अब पहले की तरह एटीएम में 2,000 रुपये के नोट नहीं डाल रहे हैं और इन्हें धीरे-धीरे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को लौटाया जा रहा है।

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष में 2017 में बैंकिंग प्रणाली में कुल नोटों में 2,000 रुपये के नोट की हिस्सेदारी 50.2 प्रतिशत थी, लेकिन 2019 में 500 रुपये के नोट की मात्रा बढ़ गई और यह 51 प्रतिशत हो गई। बैंक, एटीएम लगाने वाली और कैश लॉजिस्टिक फर्म (सीएलएफ) के कई सूत्रों ने बताया कि ये बदलाव धीरे-धीरे हो रहे हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

सीएलएफ के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, '2,000 रुपये के नोट को बंद करने जैसी कोई बात नहीं है, बस इन्हें धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। इन दिनों 500 रुपये के नोट अधिक दिख रहे हैं।' बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में तत्काल नकदी डालने के लिए 2,000 रुपये के नोट लाए गए थे। एटीएम में आवश्यक बदलाव की रफ्तार इंजीनियरों और उन्हें एक एटीएम से दूसरे एटीएम तक पहुंचने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगा। एक एटीएम दुरुस्त करने में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं।

एटीएम के परिचालन में बदलाव का तत्काल परिणाम यह होगा कि बैंक और व्हाइट-लेबल एटीएम (गैर-बैंकिंग इकाई द्वारा नियंत्रित एवं संचालित एटीएम) लगाने वाले अदला-बदली (इस समय प्रत्येक अदला-बदली पर 15 रुपये लगते हैं) के जरिये अधिक कमाई करेंगे। 2,000 रुपये के नोट हटाए जाने से ग्राहकों को बार-बार रकम निकालनी पड़ सकती है। हालांकि बताया गया है कि ग्राहक औसतन एक बार में 3,600 रुपये की निकासी करते हैं और एक बार में 10,000 रुपये तक की निकासी अपवाद होता था। सूत्रों के अनुसार इन एटीएम में नकदी डालने में आने वाला खर्च जरूर बढ़ जाएगा क्योंकि नोट ले जाने वाली गाड़ियों को अधिक चक्कर लगाने होंगे।

आर्थिक मामलों के विभाग के पूर्व सचिव सुभाष गर्ग ने नवंबर 2019 में कहा था कि 2,000 रुपये के नोट एक बड़ा हिस्सा चलन में नहीं था। लिहाजा मुद्रा लेनदेन के तौर पर 2,000 रुपये का नोट काम नहीं कर रहा है। गर्ग ने कहा था कि बैंकिंग प्रणाली से ये नोट निकालने से किसी तरह की नकदी समस्या पैदा नहीं होगी।

खबरों में रहे स्टॉक

नवीन फ्लोरीन इंटरनैशनल

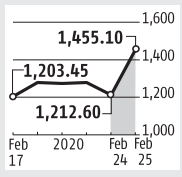

एक वैश्विक कंपनी संग 2,900 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर

₹ 1,212.60 पिछला बंद भाव
₹ 1,455.10 आज का बंद भाव
▲ 20.00 %

आईआरसीटीसी

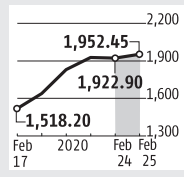

पांच सप्ताह में शेयर 103 फीसदी चढ़ा

₹ 1,922.90 पिछला बंद भाव
₹ 1,952.45 आज का बंद भाव
▲ 1.54 %

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी

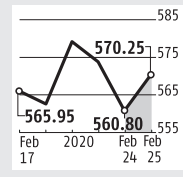

एनएसई वायदा एवं विकल्प श्रेणी में 28 फरवरी से शामिल

₹ 560.80 पिछला बंद भाव
₹ 570.25 आज का बंद भाव
▲ 1.69 %

इंटरग्लोब एविएशन

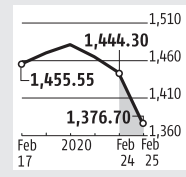

सेबी की शुरुआती जांच में संबंधित पक्ष के लेनदेन का खुलासा

₹ 1,444.30 पिछला बंद भाव
₹ 1,376.70 आज का बंद भाव
▼ 4.68 %

डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज

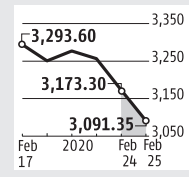

निफ्टी 50 में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 3,173.30 पिछला बंद भाव
₹ 3,091.35 आज का बंद भाव
▼ 2.58 %

संक्षेप में

बॉन्ड के जरिए 28,000 करोड़ रु. जुटाएगा हुडको

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के निदेशक मंडल की इसी सप्ताह बैठक होने जा रही है जिसमें बॉन्ड जारी कर 28,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार किया जाएगा। बंबई स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना में हुडको ने कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल की शुक्रवार को बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बॉन्ड-डिबेंचर (करमुक्त बॉन्ड और पूंजीगत लाभ बॉन्ड भी शामिल) जारी कर 28,000 करोड़ रुपये तक जुटाने पर विचार किया जाएगा। हुडको की वेबसाइट के अनुसार 2,500 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ उसकी चुकता इक्विटी 2,001.90 करोड़ रुपये है। *भाषा*

माइकल माइबैश होंगे मास्टरकार्ड के नए सीईओ

मास्टरकार्ड ने कंपनी के मुख्य उत्पाद अधिकारी माइकल माइबैश को नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नामित किया है। कंपनी ने मंगलवार को घोषणा की कि माइबैश मौजूदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 2021 से शुरू होगा। बंगा कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन होंगे। वह सेवानिवृत्त हो रहे रिचर्ड हैथॉर्नवाइटे का स्थान लेंगे। माइबैश को कंपनी के निदेशक मंडल में भी स्थान मिलेगा। *एजेंसियां*

आईआरबी के इनविट में निवेश

आईआरबी इन्फ्रा को जीआईसी से निवेश के पहले किस्त में मिले 3,753 करोड़ रुपये

अमृता पिल्लई
मुंबई, 25 फरवरी

आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने आज कहा कि उसके निजी बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट को सिंगापुर के निवेश फंड जीआईसी से निवेश के पहले किस्त के रूप में 3,753 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

कंपनी ने अपने बयान में कहा, 'आईआरबी घोषणा करती है कि उसे आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के लिए जीआईसी की 4,400 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता के तहत पहली किस्त के तौर पर 3,753 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।' कंपनी ने कहा कि शेष करीब 650 करोड़ रुपये का निवेश निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण में प्रगति के बाद किया जाएगा।

जीआईसी यह निवेश आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा शुरू किए गए एक निजी बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) में यूनिट के बदले किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि यूनिट का आवंटन 27 फरवरी 2020 तक किया जाएगा। आईआरबी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 'यूनिट के आवंटन के बाद इस निजी इनविट में आईआरबी की 51 फीसदी हिस्सेदारी होगी और जीआईसी से संबद्ध कंपनियों की हिस्सेदारी 49 फीसदी होगी।'

इस लेनदेन के तहत आईआरबी इन्फ्रा अपनी 9 बीओटी यानी निर्माण, परिचालन एवं हस्तांतरण वाली सड़क परियोजनाओं को एक निजी इनविट के तहत हस्तांतरित करेगी जिसमें आईआरबी की नियंत्रण योग्य 51 फीसदी हिस्सेदारी होगी। इन 9 सड़क परिसंपत्तियों में 900 किलोमीटर लंबी पांच परियोजनाएं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैं।

ये सभी नौ परिसंपत्तियां राजस्व सृजित करने वाली हैं और पूरी होने पर इस निजी इनविट का एंटरप्राइज मूल्य 22,500 करोड़ रुपये हो जाएगा। कंपनी ने कहा कियह 22,500 करोड़ रुपये के अनुमानित एंटरप्राइज मूल्य पर आधारित सड़क क्षेत्र का सबसे बड़ा सौदा है।

बजाज कंसल्टैंट्स इस लेनदेन के लिए आईआरबी का विशेष वित्तीय सलाहकार है। जबकि एसऐंडआर एसोसिएट्स आईआरबी का कानूनी सलाहकार और निशीथ देसाई एसोसिएट्स जीआईसी से संबद्ध कंपनियों का कानूनी सलाहकार है।

जीआईसी के मुख्य निवेश अधिकारी (बुनियादी ढांचा) एंग इंग सेंग ने कहा, 'हमें यह प्लेटफॉर्म न केवल काफी निवेश उपलब्ध कराएगा बल्कि इससे भारत में हमारी स्थिति सुदृढ़ होगी और टोल रोड का हमारा पोर्टफोलियो का विवधीकरण होगा। साथ ही यह आईआरबी को लगातार कारोबार बढ़ाने में भी मदद करेगा। भारत दीर्घावधि के लिए जीआईसी का एक प्रमुख बाजार बरकरार रहेगा क्योंकि इसकी आर्थिक बुनियाद दमदार है और यहां बुनियादी ढांचा विकास की काफी क्षमता मौजूद है।'

आईआरबी निवेश की रकम का इस्तेमाल पोर्टफोलियो का कर्ज बोझ घटाने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की इक्विटी फंडिंग में करेगी।

बुनियादी ढांचा निवेश फंड

- यूनिट के आवंटन के बाद इस निजी इनविट में आईआरबी की हिस्सेदारी 51 फीसदी होगी
- जीआईसी से संबद्ध कंपनियों की हिस्सेदारी 49 फीसदी होगी
- यूनिट का आवंटन 27 फरवरी 2020 तक किया जाएगा

कृत्रिम मेधा के पूर्वग्रह से नडेला चिंतित

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 25 फरवरी

सत्य नडेला
सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट

कृत्रिम मेधा (एआई) प्रयोग कभी कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं, यह अब कोई नई बात नहीं है और जब ऐसा हुआ है तो एआई की सबसे बड़ी समर्थकों में से एक माइक्रोसॉफ्ट इसे लेकर काफी चिंतित है।

लेकिन रेडमंड में मुख्यालय वाली इस कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी सत्य नडेला के पास ऐसे पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए सामान्य सॉल्युशन है। मौजूदा समय में भारत की तीन-दिवसीय यात्रा पर आए नडेला का कहना है कि यह एआई इंजन नहीं, बल्कि टीमें हैं जो इसका निर्माण करती हैं और साथ ही इंटेलीजेंट को विविध बनाने के लिए एल्गोरिदम तैयार करती हैं, जिससे कि उनके द्वारा तैयार सॉल्युशन किसी तरह के गैर-जरूरी पूर्वग्रह को प्रदर्शित न करें।

हैदराबाद में जन्मे नडेला ने मंगलवार को बेंगलूरु में कंपनी के 'फ्यूचर डिकोडेड' टेक समिट में बोल रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा, 'एआई को पूर्वग्रह से बचाने के लिए आपके पास विविध अनुभव वाली टीमें होना जरूरी है।'

माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा कि डेवलपरों को मानवाधिकार के तौर पर निजता के बारे में सोचना होगा, और इन प्रौद्योगिकियों का निर्माण करने वाली टीमों में लिंग और जातीय विविधता होना जरूरी है।

डेवलपर समुदाय और आईटी उद्योग के दिग्गजों की उपस्थिति वाले इस सम्मेलन में बोलते हुए नडेला ने कहा कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था को अगले 10 साल में रिटेल, हेल्थकेयर और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने की जरूरत है। नए दशक के शुरू में भारत की अपनी यात्रा पर नडेला ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का असर पिछले 10 वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से देखा गया है।

नडेला का बुधवार को नई दिल्ली में छात्रों के एक वर्ग, डेवलपरों और उद्यमियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य हरेक संगठन को नई प्रौद्योगिकी अपनाकर सॉफ्टवेयर कंपनी बनने और इसके बाद उन्हें अपनी स्वयं की डिजिटल नवीनताओं के निर्माण में मदद करना है। उन्होंने कहा, 'किसी के द्वारा की गई गलती उसके लिए सीख प्रदान कर उसके भविष्य को मजबूत बना सकती है।'

उन्होंने कहा कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का दायरा बढ़ा है, डेवलपरों और कंपनियों के लिए समाज पर इसके असर के बारे में सोचने की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। ऐसी एक जिम्मेदारी उस हरेक बैंक की तरह प्रौद्योगिकी में विश्वास पैदा करना है, जो मोबाइल ऐप बनाता है और ट्रांजेक्शन करता है। इसके लिए निजता को बढ़ावा देने और परिसंपत्तियों तथा ग्राहक डेटा के लिए साइबर सुरक्षा मुहैया कराने की भी जरूरत होगी।

हवाई अड्डों का निजीकरण फिलहाल ठंडे बस्ते में

पृष्ठ 1 का शेष...

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'निजीकरण की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। कैबिनेट सचिवालय से नियमों पर नए सिरे से काम करने का स्पष्ट निर्देश मिला है। निजीकरण पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा।'

अधिकारी ने कहा कि सरकार को इस बात की चिंता है कि अगर सभी छह हवाई अड्डे एक ही बोलीदाता के पास चले जाते हैं तो इससे गलत संकेत जाएगा और भ्रष्टाचार को लेकर संदेह पैदा होगा। फरवरी 2018 में छह हवाई अड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सरकार छह और हवाई अड्डों – अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची का निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की थी। दिसंबर 2019 में एएआई ने निजीकरण की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद निविदा के नियम और शर्तें तैयार की गईं और उसे आर्थिक मामलों के विभाग के पास भेजा गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय बोली के लिए हवाई अड्डों की संख्या सीमित करने के पक्ष में नहीं है।

अधिकारी का कहना है कि अधिकतम प्रतिस्पर्द्धा के लिए हवाई अड्डों की संख्या को सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस चरण में अपेक्षाकृत कम यातायात वाले हवाई अड्डों के लिए बोली लगाई जानी है।

आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा, 'छह हवाई अड्डा परियोजना में काफी पूंजी की जरूरत होती है, ऐसे में यह प्रावधान होना चाहिए कि एक बोलीदाता को दो से अधिक हवाई अड्डे नहीं दिए जाएंगे। विभिन्न कंपनियों को हवाई अड्डा देने से प्रतिस्पर्द्धा भी बढ़ेगी।'

निजीकरण की प्रक्रिया एएआई के लिए काफी फायदेमंद रहा है। एएआई के अनुसार अदाणी ने अहमदाबाद के लिए 177 रुपये प्रति यात्री, जयपुर के लिए 174 रुपये, लखनऊ के लिए 171 रुपये, तिरुवनंतपुरम के लिए 168 रुपये, मंगलूरु के लिए 115 रुपये और गुवाहाटी के लिए 160 रुपये प्रति यात्री देने की पेशकश की है।

कुछ मामलों में बोली की राशि दूसरे सबसे ऊंची बोली से करीब दोगुनी थी रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार, अदाणी द्वारा आक्रामक बोली लगाना एएआई के लिए अच्छा साबित हुआ। एएआई अदाणी से सालाना 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय अर्जित करेगी।

इंडस: वोडा-आइडिया व भारती इन्फ्राटेल में मतभेद

इंडस टावर में वोडाफोन आइडिया की 11.15 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री को लेकर वोडा-आइडिया और भारती समूह के बीच बातचीत में मतभेद देखने को मिले हैं। भारती इन्फ्राटेल और इंडस टावर के विलय की मंजूरी के बाद पूरी तरह नकदी में यह सौदा हो सकता है। पिछले हफ्ते इस सौदे को दूरसंचार विभाग की मंजूरी मिली थी। भारती के सूत्रों ने कहा, बातचीत हालांकि चल रही थी, लेकिन किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। *बीएस*

एसबीआई काड्र्स आईपीओ का कीमत दायरा 750-755 रुपये

सुंदर सेतुरामन और समी मोडक
मुंबई, 25 फरवरी

भारतीय स्टेट बैंक की सहायक एसबीआई काड्र्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम का कीमत दायरा 750 रुपये से लेकर 755 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कीमत दायरे के ऊपरी स्तर पर इश्यू का आकार 10,355 करोड़ रुपये होगा, जो उसे 2020 में पांचवां सबसे बड़ा देसी आईपीओ और सबसे बड़ा एशियाई आईपीओ बनाता है।

इस आईपीओ में 500 करोड़ रुपये के नए शेयर होंगे, जिसका इस्तेमाल कार्ड कंपनी अपना पूंजी आधार में करेगी। आईपीओ में ज्यादातर द्वितीयक शेयर बिक्री मूल कंपनी एसबीआई व प्राइवेट इक्विटी दिग्गज कार्लाइल करेगी।

देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक एसबीआई इस आईपीओ में 4 फीसदी हिस्सेदारी बेच रहा है, वहीं कार्लाइल 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। इस इश्यू के बाद एसबीआई की हिस्सेदारी 74 फीसदी से घटकर 70 फीसदी रह जाएगी, वहीं कार्लाइल की हिस्सेदारी 26 फीसदी से घटकर 16 फीसदी रह जाएगी। पीई फर्म ने 2017 में जनरल इलेक्ट्रिक की इकाई से 2,000 करोड़ रुपये में हिस्सेदारी खरीदी थी। उनकी हिस्सेदारी की कीमत अब बढ़कर 18,400 करोड़ रुपये हो गई है।

सूचीबद्धता के बाद एसबीआई कार्ड में सार्वजनिक शेयरधारिता 14 फीसदी होगी, जिसे तीन साल में बढ़ाकर 25 फीसदी करनी होगी।

देसी बाजार में एसबीआई कार्ड सूचीबद्ध होने वाली पहली क्रेडिट कार्ड कंपनी होगी। कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 71,000 करोड़ रुपये होगी, जो उसे भारत का 38वां सबसे मूल्यवान कंपनी बनाता है।

ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देखें तो वह एसबीआई कार्ड का मूल्यांकन एक लाख करोड़ रुपये के पार ले जाता है। मार्केट ऑपरेटरों के मुताबिक, अनअधिकृत बाजार में यह 45 फीसदी प्रीमियम यानी 1,100 रुपये पर चल रहा है।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि कंपनी के अद्भुत कारोबारी मॉडल, वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड, उच्च रिटर्न अनुपात और बढ़त की संभावना निवेशकों को उत्साहित कर रहा है।

अभी भारत में क्रेडिट कार्ड का प्रसार करीब तीन फीसदी है। एसबीआई कार्ड के प्रबंध निदेशक व सीईओ हरदयाल प्रसाद ने कहा, क्रेडिट कार्ड का कम प्रसार कंपनी को बढ़त की बड़ी संभावना की पेशकश करता है। हालांकि एसबीआई कार्ड अपनी बढ़त के लिए गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करेगा।

कई लोग इस आईपीओ को नई प्रतिभूतियों के लिए निवेशकों की स्वाभाविक इच्छा के संकेतक के तौर पर देख रहे हैं, जिस पर कोरोनावायरस के प्रसार का असर पड़ा है।

आरंभिक सार्वजनिक निर्गम का ब्योरा

- द्वितीयक बिक्री : **9,855** करोड़ रुपये। नए शेयर : **500** करोड़ रुपये। कुल आकार **10,355** करोड़ रुपये
- इश्यू प्राइस : **750-755** रुपये प्रति शेयर
- आईपीओ खुलेगा : **2** मार्च। बंद होगा : **5** मार्च
- इस साल का पांचवां सबसे बड़ा देसी आईपीओ, एशिया का सबसे बड़ा आईपीओ

कमलेश पेडणेकर

मुंबई में आईपीओ की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिनेश खारा, प्रबंध निदेशक, एसबीआई (बाएं) और एसबीआई काड्र्स के प्रबंध निदेशक हरदयाल प्रसाद

बिन्नी बंसल का फिनटेक लेनदार रुपीक पर दांव

गोल्ड लोन ऐप रुपीक ने बिन्नी बंसल व अन्य से जुटाए 6 करोड़ डॉलर

युवराज मलिक
नई दिल्ली, 25 फरवरी

सोने के बदले कर्ज देने वाले फिनटेक ऐप रुपीक ने निवेशकों से 6 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। कंपनी ने एक बयान में यह जानकारी दी। फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल ने सिलिकन वैली के निवेशक जीजीवी कैपिटल, बार्टलसमैन इंडिया इन्वेस्टमेंट्स, केवी इन्वेस्टमेंट्स व टैंगलिन वेंचर पार्टनर्स के साथ इसमें भागीदारी की है।

मौजूदा निवेशकों सिकोया इंडिया और एसेल पार्टनर्स ने भी इस दौर में हिस्सा लिया है। रुपीक ने यह नहीं बताया कि किसने कितनी रकम का योगदान किया और न ही मूल्यांकन के बारे में जानकारी दी, लेकिन सूत्रों ने कहा कि यह सौदा पांच साल पुराने स्टार्टअप का मूल्यांकन 30 करोड़ डॉलर पर पहुंचाता है।

एनबीएफसी कंपनी रुपीक की स्थापना 2015 में सुमित मनियार ने की थी। मनियार आईआईटी मुंबई के छात्र रहे हैं। उन्होंने स्टार्टअप में उतरने से पहले रेलिगेयर और जेपी मॉर्गन के साथ काम किया है।

आधुनिक उधारी ऐप रुपीक लोगों को उनकी स्वर्ण परिसंपत्तियों के बदले कर्ज देता है। कंपनी का दावा है कि इस प्रक्रिया में करीब 30 मिनट लगते हैं और पूरी तरह ऑनलाइन काम होता है। केवाईसी पूरा करने के बाद रुपीक का कर्मी आवेदक के घर या बैंक लॉकर में सोने का सर्वे करता है। मंजूरी के बाद कर्ज की रकम सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है।

बंसल ने एक बयान में कहा, मैं वास्तव में रोमांचित हूं कि कैसे रुपीक ने काफी लोग की पहुंच में औपचारिक उधारी को ला दिया है। उनके मजबूत ग्राहक और बैंकों के साथ साझेदारी का तरीका वास्तव में भारत के असंगठित गोल्ड लोन के क्षेत्र में काफी बदलाव लाने वाला है।

यह सौदा पांच साल पुराने स्टार्टअप का मूल्यांकन 30 करोड़ डॉलर पर पहुंचाता है

बीएस-6 की लागत पर तेल कंपनियों में चर्चा

अमृता पिल्लई
मुंबई, 25 फरवरी

अन्य सरकारी तेल विपणन कंपनियों के साथ मिलकर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन नए उत्सर्जन मानदंड बीएस6 के अनुरूप ईंधन के उत्पादन लागत को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रही है। कंपनी इसी साल मार्च से अपने सभी पेट्रोल पंप पर बीएस 6 ईंधन की बिक्री शुरू करने जा रही है।

बीपीसीएल के निदेशक (रिफाइनरी) आर रामचंद्रन ने आज कहा, 'हमने प्रस्तुति दी है कि हमने जो निवेश किया है उसकी भरपाई होनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि यदि इस निवेश की भरपाई प्रति लीटर लागत में परिवर्तित किया जाए तो उसमें 70 पैसे से 1.30 रुपये की वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, 'हमने बताया कि इसे हमारी कीमतों में शामिल किया जाना चाहिए।'

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपने करीब 50 फीसदी पेट्रोल पंप को बीएस 6 ईंधन के दायरे में पहले ही ला चुकी है और शेष को मार्च के मध्य तक इस दायरे में लाने की योजना है। रामचंद्रन ने कहा कि इस लागत की वसूली के लिए एक ढांचा तैयार करने के मुद्दे पर तेल कंपनियों और सरकार के बीच अनौपचारिक बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा, 'औपचारिक तौर पर कोई प्रस्तुति नहीं दी गई है।' निदेशक ने कहा कि बीपीसीएल के लिए, रिफाइनरी के उन्नयन पर कुल निवेश करीब 7,000 करोड़ रुपये होगा।

यह कोई पहला अवसर नहीं है जब तेल कंपनियों ने बीएस6 उन्नयन के लिए लागत को लेकर चिंता जताई है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन संजीव सिंह ने जनवरी में कहा था कि वृद्धि 0.5 से 1 रुपये प्रति लीटर के बीच हो सकती है।

आईएलऐंडएफएस मामले में डेलॉयट को नोटिस भेजेगा एनएफआरए

कंपनी के खिलाफ हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 25 फरवरी

राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्राधिकरण (एनएफआरए) ने आईएलऐंडएफएस फाइनैंशियल सर्विसेज के मामले में कथित गड़बड़ी के लिए डेलॉयट हस्किंस ऐंड सेल्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, किसी तरह की कार्रवाई से पूर्व पहला कदम अंकेक्षण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। इस पर काम हो रहा है।

अंकेक्षण नियामकीय निकाय ने अंकेक्षण गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट में कहा था कि डेलॉयट हस्किंस ऐंड सेल्स में गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था व प्रक्रिया अपर्याप्त व अप्रभावी थी।

प्रोफेशनल या किसी अन्य तरह के कदाचार पर एनएफआरए को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के साथ पंजीकृत सदस्यों या फर्मों के खिलाफ जुर्माना लगाने और उन्हें 6 महीने से 10 साल तक कामकाज से दूर रखने का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है।

पिछले बयान में डेलॉयट इंडिया ने कहा था, हमें भरोसा है कि अंकेक्षण का काम नियम-कानून और भारत के पेशेवर मानकों के मुताबिक हुआ है।

एनएफआरए ने अपनी समीक्षा में कहा है कि अंकेक्षक ने जरूरी एनएफआरए इस रिपोर्ट के जरिए मिले तथ्यों पर डेलॉयट से जवाब मांगेगा। प्राधिकरण ने डेलॉयट को अपनी प्रक्रिया दुरुस्त करने आदि के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है।

अंकेक्षण कंपनी ने हाल में ऐलान किया है कि वह अपने किसी भी ऑडिट क्लाइंटों को गैर-ऑडिट सेवाओं की पेशकश नहीं करेगी। कंपनी ने कहा, हमारा मानना है कि इससे अंकेक्षक की स्वतंत्रता व गुणवत्ता पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा और सार्वजनिक व कारोबारी माहौल में अस्पष्टता समाप्त करेगा, जो हमारी सेवा के बारे में ज्यादा स्पष्टता की मांग करता है।

ग्राहकों के शेयरों का दुरुपयोग रोकने के लिए बाजार नियामक ने उठाए कदम

भाषा
नई दिल्ली, 25 फरवरी

बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को ग्राहकों के शेयरों व प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग व क्लियरिंग सदस्यों के डीमैट खातों में हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) की घटना को ध्यान में रखते हुए नियामक ने अब ग्राहकों की प्रतिभूतियों के दुरुपयोग को रोकने पर कड़े नियम बना दिए हैं।

ग्राहकों की ये प्रतिभूतियां ट्रेडिंग, क्लियरिंग सदस्यों और डिपॉजिटरी भागीदारों के नियंत्रण में रहती हैं। सेबी के परिपत्र में कहा गया है कि नियामक ने इन नए प्रारूपों को शेयर बाजारों, क्लियरिंग निगमों, डिपॉजिटरी भागीदारों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया है।

इसमें कहा गया है, एक जून 2020 से ट्रेडिंग सदस्य, क्लियरिंग सदस्य अपने ग्राहकों से प्रतिभूतियों को केवल मार्जिन गारंटी के तौर पर ही रखेंगे।

ज्यादा बाजार पूंजीकरण वाली अग्रणी 100 फर्मों में आईआरसीटीसी शामिल

दीपक कोरगांवकर
मुंबई, 25 फरवरी

पिछले महीने शेयर में हुई बढ़ोतरी के कारण रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ज्यादा बाजार पूंजीकरण वाली अग्रणी 100 कंपनियों की सूची में शामिल हो गई। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग, टूरिज्म और कैटरिंग इकाई का शेयर मंगलवार को बीएसई पर 1.5 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1,952 रुपये पर बंद हुआ। पिछले महीने कंपनी का शेयर 95 फीसदी उछला जबकि बीएसई सेंसेक्स में 3 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। बीएसई के आंकड़े के मुताबिक, 31,239 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ आईआरसीटीसी का स्थान कुल बाजार पूंजीकरण की रैंकिंग में 97वां है। सूचीबद्धता के दिन 14 अक्टूबर 2019 को कंपनी का बाजार पूंजीकरण 11,658 करोड़ रुपये था और उसका स्थान सूची में 194वां था।

अभी आईआरसीटीसी का बाजार पूंजीकरण निफ्टी की दो कंपनियों ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (24,195 करोड़ रुपये) और येस बैंक (8,965 करोड़ रुपये) से ज्यादा है। इस अवधि में कंपनी एसऐंडपी बीएसई 100 इंडेक्स में शामिल एमआरएफ, ल्यूपिन, अरविंदो फार्मा, पेज इंडस्ट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, एसीसी, अशोक लीलैंड, भारत फोर्ज और टीवीएस मोटर कंपनी समेत 27 फर्मों से आगे निकल गई।

मंगलवार की तेजी के साथ आईआरसीटीसी का शेयर अपने इश्यू प्राइस 320 रुपये के मुकाबले 510 फीसदी उछला है। कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी, जो 100 फीसदी चुकता पूंजी के बराबर है। कंपनी ने लाभांश के लिए 24 फरवरी 2020 की तारीख का ऐलान किया था।

एकाधिकार वाला कारोबार

आईआरसीटीसी एकमात्र इकाई है जिसे भारतीय रेल ने रेलवे में कैटरिंग सेवा, ऑनलाइन रेल टिकट और बोतलबंद पानी रेलवे स्टेशनों व ट्रेन में उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ई-टिकटिंग सेवा में उम्दा प्रदर्शन के दम पर कंपनी का लाभ पांच गुने की उछाल के सात 193 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 36 करोड़ रुपये रहा था। कुल मिलाकर आईआरसीटीसी का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में 206 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 74 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का कुल राजस्व एक साल पहले के 435 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 716 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ई-टिकट सेवा से राजस्व चार गुना उछलकर दिसंबर तिमाही में 227 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 55 करोड़ रुपये रहा था।

एक महीने में आईआरसीटीसी का शेयर 95 फीसदी चढ़ा जबकि सेंसेक्स में 3 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई

रेलवे ने प्रीमियम व गैर-प्रीमियम ट्रेनों की कैटरिंग सेवाओं के लिए नई टैरिफ को मंजूरी दी है और संशोधित दर 28 मार्च से लागू होगी। रेलवे की योजना लंबी दूरी की ट्रेनों में पैंट्री कार जोड़ने की है, ऐसे में कैटरिंग राजस्व में इजाफा होगा।

भारतीय रेल निजी आधार पर 150 ट्रेन जोड़ने की योजना बना रहा है और आईआरसीटीसी इस परियोजना में हिस्सा ले सकती है और कंसल्टेंट की नियुक्ति कर चुकी है। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने दो रेलनीर प्लांट जोड़े हैं और मौजूदा तिमाही में दो और प्लांट जोड़ेगी। यह कहना है नारनोलिया फाइनैंशियल एडवाइजर्स के विश्लेषकों का।

संक्षेप में

दिसंबर में 12.67 लाख नई नौकरियां मिलीं

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 में करीब 12.67 लाख नौकरियां सृजित हुईं, जबकि इससे पिछले महीने में 14.59 लाख नौकरियां सृजित हुई थीं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने एक रिपोर्ट में कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ईएसआईसी के साथ कुल 1.49 करोड़ नए कर्मचारियों/ श्रमिकों के नामांकन कराए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सितंबर 2017 से दिसंबर 2019 के दौरान लगभग 3.50 करोड़ नए लोग ईएसआईसी योजना में शामिल हुए। *भाषा*

850 करोड़ रुपये का मसाला बॉन्ड सूचीबद्ध

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 850 करोड़ रुपये के दस वर्षीय मसाला बॉन्ड को इंडिया आईएनएक्स के वैश्विक ऋण पत्र प्लेटफार्म में सूचीबद्ध किया है। इस बॉन्ड पत्र से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल भारत में निवेश और स्थानीय मुद्रा में ऋण के लिए किया जाएगा। बीएसई के स्वामित्व वाले इस एक्सचेंज ने मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में यह कहा। इंडिया आईएनएक्स देश का पहला अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज है जो कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित है। यह केंद्र गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थित है। *भाषा*

मॉरिशस से नए एफपीआई पंजीकरण को होगी अनुमति

सेबी ने एफपीआई की बढ़ी हुई निगरानी को लेकर आशंकाओं को खत्म करने के लिए दी सफाई, निगरानी बढ़ाएगा नियामक

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 25 फरवरी

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)ने आज कहा है कि मॉरिशस के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की बढ़ी हुई निगरानी के साथ पंजीकरण की योग्यता बनी रहेगी।

इस स्पष्टीकरण से खासी राहत मिली है। सरकार के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने धनशोधन निरोधक मानक तय किए हैं, जिसकी वजह से मॉरिशस को 'ग्रे लिस्ट' में डाल दिया गया है, जिसे लेकर बाजार के कारोबारियों में अनिश्चितता पैदा हो गई थी। एक बड़े विदेशी कस्टोडियन ने सोमवार को मॉरिशस के कारोबारियों को रोक दिया था और यह चिंता जताई जा रही थी कि अन्य भी ऐसा ही करेंगे व सभी नए पंजीकरण व मॉरिशस के माध्यम से खरीद रोक दी जाएगी।

एक अन्य कस्टोडियन ने एक नोट जारी कर कहा था कि मॉरिशस से इस समय पंजीकृत एफपीआई को इक्विटी, डेट और हाइब्रिड सिक्योरिटी या नए डेरिवेटिव्स पोजिशन में 28 फरवरी से अनुमति नहीं दी जाएगी। कस्टोडियंस ने खरीद के लिए ऐसे एफपीआई के खातों को ब्लॉक कर दिया था और सिर्फ कारोबारियों को बिक्री की अनुमति दी थी।

कस्टोडियंस ने इसके लिए सेबी से स्पष्टीकरण की मांग की थी। वे चाहते थे कि सेबी अधिसूचना पर फिर से विचार करे। जब अधिकार क्षेत्र को 'ग्रे लिस्ट' में डाल दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि देश चिह्नित की गई रणनीतिक खामियों का समाधान सहमति के मुताबिक तय समयसीमा में करने को प्रतिबद्ध है और यह बढ़ी हुई निगरानी के अधीन है।

मंगलवार को सेबी की ओर से जारी एक नोट में कहा गया है, 'एफएटीएम ने बढ़ी हुई कानूनी जरूरतों के लिए आवेदन की मांग नहीं करेगा, जो इन अधिकार क्षेत्रों पर लागू होगा, बल्कि उसने अपने सदस्यों को अपने जोखिम विश्लेषण के बारे में सूचनाएं रखने को प्रोत्साहित किया है। इंटरमीडिएटरीज को भी इसे संज्ञान में लेना चाहिए।'

सेबी के मौजूदा दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एफएटीएफ द्वारा चिह्नित किए गए रणनीतिक धनशोधन निरोधक या आतंकी वित्तपोषण की खामियों वाले निवेशकों को एफपीआई के रूप में पंजीकरण के योग्य नहीं माना जाएगा। एफपीआई ऐसे अधिकार क्षेत्र से नहीं होने चाहिए, जिसने इन खामियों को दूर करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या ऐसा करने के लिए कार्ययोजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।

खेतान ऐंड कंपनी में पार्टनर दिवास्पति सिंह ने कहा, 'एफएटीएफ ने जहां मॉरिशस को बढ़ी निगरानी की सूची में डाल दिया है, इसमें वित्तीय रोक या प्रतिबंधों की बात नहीं की गई है। इस हिसाब से तात्कालिय नियामकीय प्रभाव सीमित हो सकता है।' बहरहाल उन्होंने कहा कि ग्रे लिस्ट का हिस्सा होने की वजह से धारणा संबंधी बड़ा मसला बनेगा, खासकर बड़े निवेशकों जैसे पेंशन, एंडाउनमेंट और सॉवरिन वेल्थ फंड के मामलों में, जिनका निवेश चार्टर मॉरिशस के माध्यम से निवेश को प्रतिबंधित कर सकता है।

पिछले साल से मॉरिशस अंतरराष्ट्रीय कर मानकों के अनुपालन की कवायद कर रहा है। इसमें ऑफशोर फंड ढांचों की जांच की दिशा में कदम बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं।

एफएटीएफ ने पाया, '2018 में एमईआर (म्युचुअल इवैलुएशन रिपोर्ट) पूरा करने के बाद मॉरिशस ने अपने एमईआर में कार्रवाई को लेकर की गई सिफारिशों की दिशा में कई प्रगति की है। वहां कानूनी ढांचे व कानूनी व्यवस्थाओं सहित तकनीकी अनुपालन में सुधार की है, जिससे अपराधों को रोका जा सके।'

विशेषज्ञों का कहना है कि मॉरिशस के करीब 80 प्रतिशत एफपीआई को पहले ही सेबी ने श्रेणी 2 में वर्गीकृत कर रखा है। ग्रे सूची के दर्जे से इन फंडों के श्रेणी 1 में आने की उमी धूमिल होती है। उन्होंने कहा कि शेष 20 प्रतिशत फंड, जो श्रेणी 1 में हैं, वह भी नई स्थिति के कारण श्रेणी 2 में जा सकते हैं।

ग्रे सूची और काली सूची में डाले जाने में है अंतर

ग्रे सूची

- अधिकार क्षेत्र को बढ़ी निगरानी के तहत डाला जाता है
- देश खामियों को चिह्नित करने व उनके समाधान की प्रतिबद्धता जताता है
- एफएटीएफ अन्य सदस्यों पर बढ़े अनुपालन का दबाव नहीं बनाता
- बहरहाल उन्हें अपने जोखिम विश्लेषण संबंधी सूचनाएं बढ़ाने को करता है प्रोत्साहित

काली सूची

- अपनी शासन पद्धति में उल्लेखनीय खामियां रखने वाले देश
- वे, जो धन शोधन और आतंकवादियों को वित्तपोषण रोकने में असफल रहते हैं
- एफएटीएफ सदस्यों से अनुरोध करता है कि बढ़े हुए अनुपालन को लागू करें
- ज्यादा गंभीर मामलों में देश को जवाबी कदम को लेकर आवेदन करने को कहा जाता है

जीएसटी में संदिग्ध लेन-देन बढ़ा

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 25 फरवरी

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने आज कहा कि वह जीएसटी उपकर को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि लक्षित कर संग्रह न हो पाने के कारण केंद्र सरकार राज्य का फरवरी-मार्च 2020 का 11,000 करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजे का भुगतान रोक सकती है।

मित्रा ने सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, 'मेरी बड़ी चिंता यह है कि फरवरी-मार्च के लिए भुगतान नहीं मिलेगा।' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 21 प्रतिशत उपकर संग्रह का लक्ष्य रखा है, वहीं यह संग्रह करीब 1.5 प्रतिशत है। मित्रा के मुताबिक राज्य को जहां वित्तीय मसलों से जूझना पड़ रहा है और वैकल्पिक योजनाओं पर काम करना पड़ रहा है वहीं केंद्र सरकार उपकर और अधिभार बढ़ा रही है, जिसमें राज्यों को कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है।

उन्होंने आरोप लगाया, 'राज्यों को निचोड़ा जा रहा है। उपकर लगातार बढ़ रहा है। यह 2013-14 में 6 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है। यह देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। यह प्रतिमान में बदलाव है और देश के संघीय ढांचे को चुनौती दी जा रही है।' करों से इतर उपकर और अधिभार में केंद्र से राज्यों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। मंत्री ने आरोप लगाया कि जीएसटी की त्रुटिपूर्ण डिजाइन के चलते कराधान में धोखाधड़ी बढ़ रही है।

उन्होंने कहा, 'जीएसटी संग्रह में धोखाधड़ी करने के लिए लोग फर्जी कंपनियां बना रहे हैं। बगैर किसी परीक्षण के जीएसटी जल्दबाजी में लागू कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि धोखाधड़ी वाले लेन देन देश भर में हो रहे हैं। संदेहास्पद लेन-देन की संख्या बढ़ रही है।'

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा था कि जीएसटी पर अनरिकवर्ड जुर्माने वाला ब्याज 46,000 करोड़ रुपये है और धोखाधड़ी की राशि बढ़कर 44,000 करोड़ रुपये हो गई है। मित्रा के मुताबिक यह जुर्माने वाला ब्याज कारोबारियों द्वारा जीएसटीआर 3 बी फाइलिंग में देरी की वजह से नजर आ रहा है।

> राज्यों को निचोड़ा जा रहा है। उपकर बढ़कर 2013-14 के 6 प्रतिशत की तुलना में अब 18 प्रतिशत हो गया है। यह देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है

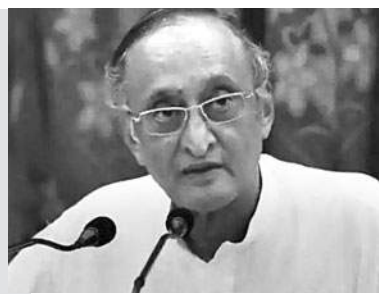

वित्त वर्ष 21 में 9 फीसदी तक होगी ऋण वृद्धि

सुब्रत पांडा
मुंबई, 25 फरवरी

मौजूदा वित्त वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली ऋण प्राप्ति में मंदी में कमी आने के संकेत दिखाई दे सकते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष (21) के दौरान सकल ऋण प्राप्ति में 200 से 300 आधार अंकों का इजाफा हो सकता है जिसे आर्थिक गतिविधियों में सुधार, खुदरा ऋण प्रतिभूतिकरण की निरंतर मांग में तेजी के कारण बढ़ावा मिल सकता है।

वित्त वर्ष 20 में ऋण वृद्धि दर छह प्रतिशत के आसपास चल रही है, जो पिछले कई सालों में सबसे कम है। वित्त वर्ष 19 में ऋण वृद्धि दर 11 प्रतिशत थी और वित्त वर्ष 18 में यह नौ प्रतिशत थी। रेटिंग एजेंसी को यह भी उम्मीद है कि तीन तिमाहियों की नरमी के बाद चौथी तिमाही के दौरान रफ्तार में कुछ तेजी आएगी।

ऋण वृद्धि में यह तेजी निजी क्षेत्र के बैंकों की अगुआई में होगी क्योंकि उनके ऋण उठाव की वृद्धि लगभग 15 प्रतिशत के आस-पास रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे उनके सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी बैंकों की तुलना में बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है जिसे उनकी पूंजी की मजबूत स्थिति और पूंजी जुटाने की क्षमता से मदद मिलती है। क्रिसिल का कहना है कि 31 मार्च, 2019 के मुकाबले 31 मार्च, 2021 तक उनकी हिस्सेदारी में लगभग 400 आधार अंक वृद्धि होने की उम्मीद है।

इसके अलावा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दीर्घावधि रीपो परिचालन (एलटीआरओ) शुरू करने का कदम उठाया है ताकि बैंकों की कोष लागत में कमी लाई जा सके। इससे बैंकों की ऋण देने की कवायद को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उन्हें खुदरा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों को वृद्धिशील ऋण देने के लिए नकद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने से छूट मिल जाएगी। इससे बैंक सस्ती दर पर अधिक ऋण दे सकेंगे क्योंकि वे रीपो दर पर उधार लेंगे और जमा दरों में छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। क्रिसिल के अनुसार इस वित्त वर्ष में दिसंबर 2019 तक वृद्धिशील कुल ऋण घरेलू ऋण पिछले साल की तुलना में केवल 20 प्रतिशत है। खुदरा खंड और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीसी) को दिए जाने वाले ऋण में अच्छी वृद्धि देखी गई है, जबकि कंपनियों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले ऋण में गिरावट आई है। अगले वित्त वर्ष (21) के दौरान खुदरा ऋण वृद्धि में करीब 16 प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान है। दूसरी तरफ वित्त वर्ष 21 में कंपनियों को दिए जाने वाले बैंक ऋणों, जिनमें एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक ऋण शामिल नहीं है, में नरमी रहने की संभावना है।

अगले वित्त वर्ष में बैंक ऋण में सुधार के संकेत

- बैंक ऋण में नरमी के कारण मौजूदा वित्त वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ा है प्रतिकूल असर
- वित्त वर्ष 21 में सकल ऋण में 200 से 300 आधार अंक इजाफा के आसार
- वित्त वर्ष 20 में ऋण वृद्धि दर चल रही छह प्रतिशत के आसपास, पिछले कई सालों में सबसे कम
- वित्त वर्ष 19 में 11 प्रतिशत और वित्त वर्ष 18 में नौ प्रतिशत थी ऋण वृद्धि दर

मूल्य नियंत्रण के तहत आने वाली दवाओं की घट रही हिस्सेदारी

सोहिनी दास
मुंबई, 25 फरवरी

भारत के कुल घरेलू दवा बाजार में मूल्य नियंत्रण के तहत आने वाली दवाओं की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों से कम हो रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2014-15 में घरेलू बाजार में इनकी कुल हिस्सेदारी 17 प्रतिशत थी, जो वित्त वर्ष 19 में घटकर 14 प्रतिशत रह गई है। वित्त वर्ष 2020 में भी यही धारणा जारी है।

बाजार शोध फर्म एआईओसीडी एडब्ल्यूएसीएस के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि के दौरान भारत का दवा बाजार 86,410 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल की गई दवाओं के अधिकतम मूल्य के निर्धारण में भारत बाजार आधारित व्यवस्था का पालन करता है। देश के दवाओं के दाम का नियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) समय समय पर इस सूची को अद्यतन करता है। दो दवाएं मूल्य नियंत्रण के दायरे में आती हैं उन्हें अनुसूचित दवाएं कहा जाता है। अन्य सभी दवाओं के मामले में फर्मों को 10 प्रतिशत तक दाम बढ़ाने की अनुमति है।

इंडिया इन्फोलाइन (आईआईएफएल) के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि एनईएलएम के तहत आने वाली दवाओं की हिस्सेदारी कुल घरेलू दवा बाजार के प्रतिशत के हिसाब से घट रही है। आईआईएफएल ने कहा है, 'मूल्य के हिसाब से सिर्फ 14 प्रतिशत दवा बाजार इस समय मूल्य नियंत्रण के दायरे में आता है।'

दवाओं के मूल्य नियंत्रण की स्थिति में ब्रोकरेज का मानना है कि बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां अपनी भारतीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में घाटे में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके उत्पादों के दाम बाजार के प्रीमियम के हिसाब से तय होती हैं और अगर कोई सीलिंग लगाई जाती है तो एमएनसी को अपनी दवाओं के दाम अन्य की तुलना में बहुत ज्यादा घटाने होते हैं।

दूसरे, एमएनसी की ओर से पेश किए गए उत्पाद की दर भारतीय कंपनियों की तुलना में कम होती है। ऐसे में मूल्य नियंत्रण का जोखिम एमएनसी को रहता है।

इसमें कहा गया है कि बड़े ब्रॉन्डों को बेहतर मुनाफा होता है, वहीं मूल्य नियंत्रण स्वाभाविक रूप से उन कंपनियों पर ज्यादा असर डालता है, जिनके अपने बड़े ब्रॉन्ड हैं। दूसरी तरफ भारतीय फर्में मूल्य नियंत्रित उत्पाद को छोड़कर गैर मूल्य नियंत्रण वाले उत्पाद की ओर बहुत तेजी से चली जाती हैं। यह पेश किए गए नए ब्रॉन्डों के आंकड़े से पता चलता है कि कि सतर से फर्मों ने अपने पोर्टफोलियो को तार्किक बनाने की कवायद की है। वित्त वर्ष 15 में जहां 3,836 ब्रॉन्ड पेश किए गए, वहीं वित्त वर्ष 19 में 2,662 ब्रॉन्ड पेश किए गए।

नए ब्रॉन्ड की दवाएं पेश करने में डर्मेटोलॉजी, विटामिन-मिनरल्स-न्यूट्रिएंट्स और गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी क्षेत्र प्रमुख हैं।

प्रमुख दवा कंपनी कैडिला हेल्थकेयर वित्त वर्ष 2018-19 में 100 ब्रॉन्ड वापस लिए जबकि उसने 50 नए ब्रॉन्ड पेश किए। अहमदाबाद की एक दवा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अगर किसी ब्रॉन्ड को एनईएलएम में डाल दिया जाता है तो कोई उस ब्रॉन्ड का उत्पादन नहीं रोक सकता, लेकिन कंपनियां हर साल उनकी मात्रा कुछ कम कर देती हैं। इस तरह से उसकी मात्रा कम कर दी जाती है और रणनीतिक कदम के तहत कंपनियां धीरे धीरे उसकी मात्रा व मुनाफा कम करते करते उस ब्रॉन्ड को गायब कर देती हैं।'

हाल ही में 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में भारत की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था में विसंगतियां सामने आई थीं। इसमें कहा गया था, 'औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 2013 के माध्यम से दवाओं के मूल्य के नियमन से नियमन के दायरे वाली दवाओं के दाम उन दवाओं की तुलना में ज्यादा बढ़े हैं, जिनके दाम नियंत्रण के दायरे में नहीं आते हैं।'

दवा उद्योग ने आर्थिक समीक्षा के गणना के तरीकों को चुनौती दीहै। एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कहा कि भारत में एनईएलएम के तहत आने वाली दवाओं और मूल्य नियंत्रण को अलग किया जाना चाहिए। एनईएलएम मे दवाओं की पहुंच और सस्ती दवाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजार की ताकतें मूल्य को नियंत्रण में रखती हैं।

कुल घरेलू बाजार के प्रतिशत के हिसाब से लगातार घट रही है एनईएलएम की हिस्सेदारी

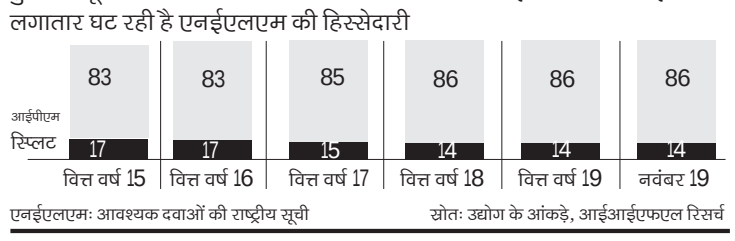

एनईएलएमः आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची — स्रोतः उद्योग के आंकड़े, आईआईएफएल रिसर्च

बुंदेलखंड में पाइपलाइन से होगी पेयजल आपूर्ति

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 25 फरवरी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार समूचे बुंदेलखंड के गांवों और शहरों में पाइप के जरिये पेयजल की आपूर्ति करेगी। प्रदेश सरकार इस परियोजना पर 15,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में पुलिस एवं फॉरेंसिक विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दी गई। साथ ही बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को पाइप लाइन से पानी पहुंचाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले सभी सातों जिलों और विंध्य क्षेत्र के दो जिलों में सौ फीसदी पेयजल की आपूर्ति पाइप लाइन के जरिये की जाएगी। इस परियोजना पर काम शुरू हो गया है और अब तक सभी नौ जिलों की 545 डीपीआर तैयार कर ली गई हैं।

इसी साल 18 फरवरी को पेश किए गए प्रदेश सरकार के बजट में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। मंगलवार को मंत्रिपरिषद ने इस आशय के प्रस्ताव को पारित करते हुए पुलिस एवं फॉरेंसिक साइंस विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इसके लिए राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में 15 एकड़ भूमि चिह्नित कर पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को 350 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है।

मंत्रिपरिषद की आज की बैठक में गृह विभाग, वित्त विभाग और परिवहन विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्रदेश में एक नए आयुष विश्वविद्यालय के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस विश्वविद्यालय से प्रदेश के सभी आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजों को जोड़ा जाएगा।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 9

उम्मीद जगाती यात्रा

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की पहली भारत यात्रा इस लिहाज से उल्लेखनीय रही कि उन्होंने विवादित ट्वीट करने से परहेज किया, पहले से तय स्क्रिप्ट पर चले और न्यूनतम एजेंडा हासिल कर लिया। यात्रा के दौरान तीन अरब डॉलर का रक्षा सौदा और काफी दिखावा होने के साथ इस साल आगे चलकर एक व्यापार सौदे का वादा भी किया गया। यह अलग बात है कि औपचारिक वार्ता के बाद व्यापार सौदे को लेकर किसी भी प्रगति की घोषणा नहीं हुई। दुनिया के सर्वाधिक ताकतवर शख्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'मजबूत' नेता, 'मुश्किल वार्ताकार' और 'बेहद धार्मिक व्यक्ति' का खिताब भी मिला। गहरी निजी कूटनीति दोनों नेताओं की पसंदीदा शैली रही है और यह यात्रा भी दोनों देशों के बीच सद्भावना का माहौल बनाने में सफल रही है।

दोनों देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समेत तीन सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को 'समग्र वैश्विक भागीदारी' के स्तर तक पहुंच जाने की घोषणा भी की। यह संकेत है कि भारत-अमेरिका संबंध द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय आयामों से आगे बढ़ते हुए वैश्विक स्तर पर सम्मिलित हित की मंशा रखते हैं। भले ही इस नए रिश्ते की रूपरेखा परिभाषित नहीं की गई है लेकिन इससे ब्लू डॉट नेटवर्क में भारत की करीबी भागीदारी के संकेत जरूर मिलते हैं। अमेरिका ने चीन की बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव योजना के जवाब में ब्लू डॉट नेटवर्क की संकल्पना रखी है।

हालांकि काफी खर्चीले दिखावे के बावजूद भारत के लिए इस यात्रा के नतीजे बहुत ठोस नहीं रहे हैं। पहली बात, ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपने अच्छे संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने चीन के साथ सीमित कारोबारी सौदे का जिक्र करते हुए कहा कि वह इसे भारत के साथ सौदे का एक प्रारूप बनाना चाहते हैं।

ट्रंप के संबोधन में अमेरिका एवं भारत के बीच 16.9 अरब डॉलर के व्यापार घाटे का उल्लेख नहीं हुआ। दोनों ही पक्ष कृषि उत्पादों, मेडिकल उपकरणों, डिजिटल व्यापार और नए शुल्कों को लेकर बंटे रहे और ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि भारत के आयात शुल्क काफी अधिक हैं। तीसरी बात, उन्होंने अमेरिका में भारतीय निवेश बढ़ाने की बात कर भारतीय अधिकारियों को शायद निराश कर दिया होगा जो अमेरिका से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे।

जब दोनों नेता एक-दूसरे को गले लगा रहे थे उस समय नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं हो रही थी। अमेरिकी दूतावास में हुए संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज में अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया और कोरोनावायरस से निपटने के बारे में खुलकर बात की और इस दौरान विपक्षी डेमोक्रेट नेताओं पर भी निशाना साधा। लेकिन उन्होंने सीएए और अनुच्छेद 370 जैसे विवादित मुद्दों से दूरी बनाना ही मुनासिब समझा। ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश दोहराने के साथ ही कहा कि इस मुद्दे के कई पहलू हैं। द्विपक्षीय वार्ताओं में सीएए और अनुच्छेद 370 पर भी चर्चा हुई लेकिन ट्रंप ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह लोगों को धार्मिक आजादी देने के पक्ष में हैं। संभवत: यही इस संवाददाता सम्मेलन का सबसे अहम बिंदु था।

कुल मिलाकर उनके इस दौरे को पूरी तरह नाकाम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में सलामी गारद, अहमदाबाद के कार्यक्रम और रात्रिभोज को उल्लेखनीय सफलता नहीं माना जा सकता है। कम से कम उनके इस दौरे ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है और सभी अहम व्यापार वार्ताएं ठंडे बस्ते में नहीं चली गई हैं। एक स्थिर अर्थव्यवस्था में इसे उम्मीद का संकेत माना जा सकता है।

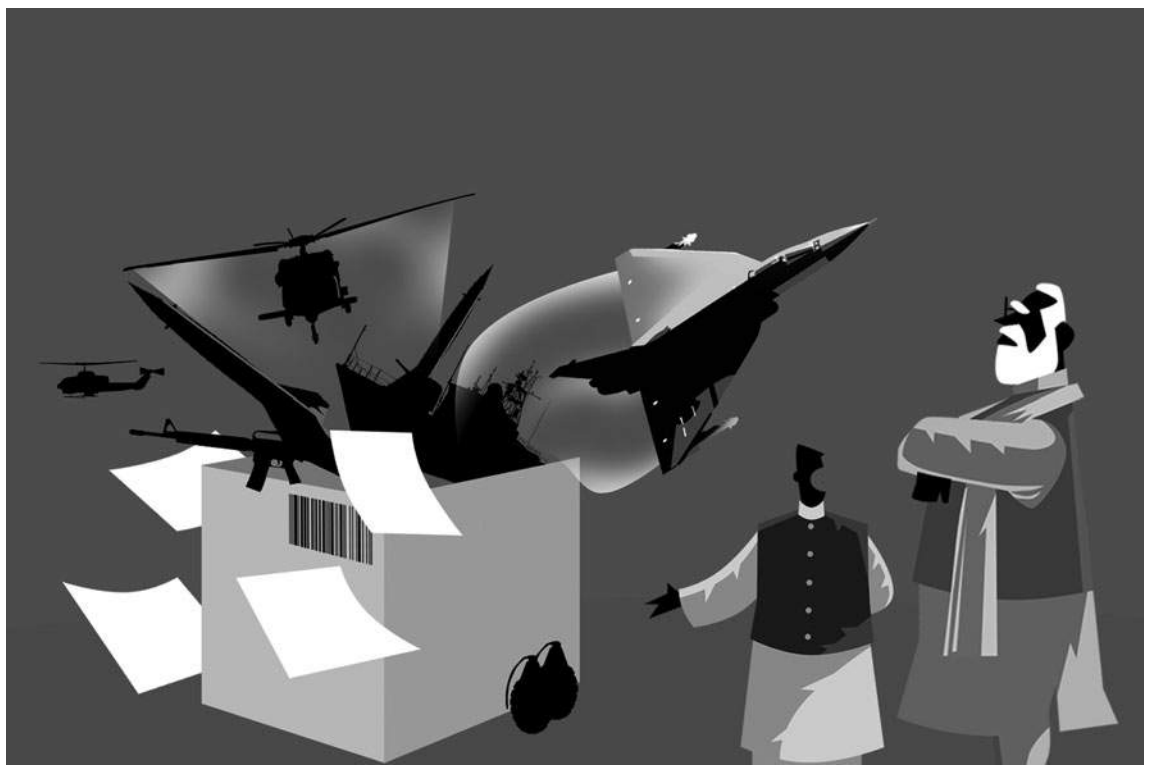

बिनय सिन्हा

रक्षा क्षेत्र के लक्ष्य और हमारी तैयारी

यदि भारत को रक्षा क्षेत्र के निर्यात में इजाफा करना है तो सबसे पहले उसे यह समझना होगा कि निर्यात और उत्पादन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं प्रेमवीर दास

हाल ही में लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो में प्रधानमंत्री ने भारतीय विनिर्माताओं से कहा कि वे अगले पांच वर्ष में रक्षा निर्यात को दोगुना बढ़ाकर 5 अरब डॉलर (37,000 करोड़ रुपये) तक करें। इस दौरान ऐसी रिपोर्ट भी हैं जो संकेत देती हैं कि निजी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी जो बड़े सैन्य प्लेटफॉर्म निर्माता बनने की इच्छा रखती थी, का नकदीकरण हो गया है और सरकार को उसकी तमाम बैंक गारंटियों को भुनाना पड़ा। ये दोनों बातें असंगत हैं और इन पर चर्चा की आवश्यकता है।

वर्ष 2011 में नौसेना ने पांच ऑफशोर पैट्रोल वैसल्स (ओपीवी) यानी अपतटीय गश्ती पोत का ऑर्डर एक निजी कंपनी पीपावाव डिफेंस ऐंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया। नौसैनिक प्लेटफॉर्म में सबसे साधारण माने जाने वाले ये पोत 2,500 करोड़ रुपये की लागत में बनने थे और इनकी आपूर्ति 2014-15 से शुरू होनी थी। वर्ष 2015 तक कंपनी का परिचालन बंद हो गया और रिलायंस नेवल ऐंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने उसका अधिग्रहण कर लिया। जुलाई 2017 में आर-नेवल ने दो ओपीवी लॉन्च किए, हालांकि ये निर्माण की स्थिति में नहीं थे। इस कंपनी ने उन्नत युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने का दम भरने वाली कंपनी ने अब दिवालिया होने का आवेदन दिया है। रक्षा मंत्रालय ने तमाम बैंक गारंटियों को नकदीकृत करते हुए युद्धपोतों के लिए 980 करोड़ रुपये का भुगतान किया था लेकिन पोतों का कहीं अता-पता नहीं है। ऑर्डर रद्द हो गया और एक भी पोत की आपूर्ति नहीं हुई। इसके बावजूद यदि किसी नेवल प्लेटफॉर्म के निर्यात की संभावना है तो ओपीवी उनमें शीर्ष पर हैं।

यह एक नौसैनिक अनुभव है। एक अन्य निजी स्वामित्व वाला शिपयार्ड भी उत्पादक बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। केवल लार्सन ऐंड टुब्रो ने प्रगति की है। सबसे पहले उसने हमारी परमाणु पनडुब्बियों का ढांचा तैयार किया और उसके बाद कुछ पारंपरिक युद्धपोत बनाए। अन्य दो सेवाओं की तस्वीर भी अलग नहीं है। निजी क्षेत्र का कोई समूह सामान्य विमान या हेलीकॉप्टर बनाने की स्थिति में भी नहीं है। हकीकत में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड (एचएएल) नामक सरकारी कंपनी ही दशकों से सामान्य लड़ाकू विमान बना रही है। वह भी वायुसेना की जरूरत के मुताबिक उनका निर्माण नहीं कर पा रही है। इनमें से किसी का निर्यात करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे द्वारा तैयार किए डिजाइन वाले लड़ाकू विमान तेजस और एएलएच हेलीकॉप्टर के मामले में निर्माण क्षमता हमारी जरूरतों से भी कम है। मौजूदा क्षमताओं के साथ उत्पादन में जबरदस्त तेजी लाना बहुत अधिक महत्त्वाकांक्षी है। कहने का अर्थ यह कि निर्यात के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जहां तक सेना की बात है तो इकलौता स्वदेशी प्लेटफॉर्म अर्जुन टैंक है लेकिन वह ऐसे अधिकांश देशों के लिए अनुकूल ही नहीं है जो अपने टैंक नहीं बनाते। कई अन्य सिस्टम मसलन बीएमपी और टी90 टैंक आदि लाइसेंस के अधीन बनते हैं और उनके निर्यात की इजाजत की संभावना बहुत कम है।

संक्षेप में कहें तो ऐसा कोई सैन्य प्लेटफॉर्म नहीं है जो संभावित निर्यातक हो सकता हो। एक संभावना यह है कि एम 77 हॉवित्जर गन को महिंद्रा एक अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर बनाए, बशर्ते कि अनुबंध इसकी इजाजत दे और पहले हमारी सेना की जरूरत पूरी हो। ऐसे में राइफल, गोली-बारूद, हथगोले, छोटी तोपों जैसी सामग्री बचती हैं। इनमें काफी इजाफा हो जाए तो भी हम तय लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं मान रहा हूं कि अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम निर्यात सूची में नहीं आ रहे हैं। प्रश्न यह है कि यहां से हम कहां जाएंगे।

रक्षा क्षेत्र की तमाम सरकारी कंपनियां वर्षों से काम कर रही हैं और उन्होंने कौशल और ज्ञान हासिल किया है। भले ही यह गुणात्मक और मात्रात्मक या दोनों ही रूप में हमारी सेना के लिए अपर्याप्त हो। इन क्षमताओं को हासिल करने में वक्त लगता है और यह मानना उचित नहीं कि निजी कंपनियों को इसे हासिल करने में इतना ही समय नहीं लगेगा। केवल विदेशी विनिर्माताओं के साथ गठजोड़ करने से क्षमता हासिल नहीं होगी। सवाल यह भी है कि कोई भी संभावित खरीदार भला लॉकहीड मार्टिन या बोइंग जैसे मूल विक्रेता से ही खरीद क्यों नहीं करेगा? इस संदर्भ में चयन डीपीएसयू क्षेत्र की मजबूती (जिसके पास क्षमताएं हैं भले ही वे असंतोषजनक हैं) या निजी क्षेत्र में सक्रिय निवेश के बीच ही करना होगा। इसके अलावा इन दोनों का सम्मिश्रण भी काम आ सकता है।

मौजूदा नीतियों में एक विशिष्ट भारतीय साझेदार को चिह्नित करना पड़ता है जो विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ गठजोड़ करता है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं न तो डीपीएसयू और न ही निजी क्षेत्र की कंपनी इस क्षेत्र की तकनीकी बाधाओं को पार कर सकती है। इसका हल संयुक्त उपक्रम में निहित है। परंतु यह कहना आसान है और करना मुश्किल। दोनों क्षेत्रों का काम करने का तरीका और अनुशासन काफी अलग है। सरकारी क्षेत्र में जहां उपयोगकर्ता लक्ष्य तय करता है और कंपनी उसे पूरा करने का काम करती है वहीं निजी कंपनियों के लिए मुनाफा सबसे अहम है। परंतु इनका मिलना आसान नहीं है। केवल सख्त नीतियों का कड़ाई से किया गया क्रियान्वयन ही इससे जुड़ी दुविधा दूर कर सकता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ऐसा करने की राजनीति इच्छाशक्ति भी है या नहीं। कुल मिलाकर भारत के रक्षा प्लेटफॉर्म निर्माता या बड़ा हथियार निर्यातक बनने की संभावना बहुत सीमित है।

हमारी अपर्याप्तता की एक वजह यह भी है कि हम विभिन्न सेनाओं द्वारा चाहे गए हथियार और प्लेटफॉर्म डिजाइन कर पाने में नाकाम रहे हैं। बीते दशकों के दौरान नौसेना में कुछ विशेषज्ञता हासिल की गई है लेकिन शेष दो शाखाओं में ऐसा नहीं हुआ है। ध्यान रहे इन शाखाओं में यह जिम्मेदारी रक्षा शोध एवं विकास संस्थान (डीआरडीओ) की है। मिसाइल तंत्र के अलावा इस क्षेत्र में कमजोरी बनी रही है। इसे हमें देश में ही विकसित करना होगा क्योंकि विदेशी आपूर्तिकर्ता कभी विशेषज्ञता नहीं हस्तांतरित करते। हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए क्षमता निर्माण क्योंकि उसके बिना हम रक्षा क्षेत्र में कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। निर्यात तो दूर की बात है।

कोरोनावायरस का खतरा मगर शोध एवं विकास का मौका

तकनीकी तंत्र

देवांशु दत्ता

कोरोनावायरस महामारी कोविड-2019 से अब तक 2,600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 75,000 से अधिक संक्रमित हुए हैं। इसे रोकने का कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ है। संकट का एक सकारात्मक पहलू यह हो सकता है कि इससे टीके पर शोध और इसके विकास की प्रक्रियाओं की समीक्षा हो सकती है। इससे नए टीकों का विकास और इस्तेमाल तेजी से होगा।

अमूमन, किसी नए टीके को प्रयोगशाला से दुकानों तक पहुंचने में दस साल का समय लगता है। इसमें प्रीक्लीनिकल डेवलपमेंट, क्लिनिकल विकास के तीन चरण, प्रीरजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन और फिर इसे बाजार में उतारने की प्रक्रिया होती है। नई प्रौद्योगिकी, त्वरित क्लीनिकल परीक्षणों और त्वरित नियामकीय मंजूरियों से कोविड-2019 के मामले में यह प्रक्रिया 12 से 18 महीने में निपट सकती है।

सामान्य कोशिकाओं के उलट वायरस आरएनए या डीएनए के छोटे अंश होते हैं जो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी इंसान, जानवर या पक्षी की कोशिकाओं पर हमला करते हैं। उनके आकार तरह-तरह के होते हैं। कोविड-2019 जैसे कोरोनावायरस आरएनए आधारित होते हैं।

कोविड-2019 खुद को किसी कोशिका से जोड़ने के लिए प्रोटीन की कुंडलित स्पाइक का इस्तेमाल करती है। जब यह स्पाइक कोशिका से जुड़ जाती है तो यह एकदम सीधी हो जाती है और कोशिका में घुसने के लिए छेद करती है। इसके बाद वायरस अपना प्रतिरूप बनाने के लिए मेजबान शरीर को चकमा देता है और उसे लगता है कि वायरस वैध आनुवंशिक निर्देश दे रहा है।

शरीर वायरस के विशेष आकार को पहचानकर उससे लड़ने के लिए ऐंटीबॉडी विकसित करता है। अगर शरीर विशेष आकार के वायरस के एक हिस्से की भी पहचान करता है तब भी ऐंटीबॉडी काम करती हैं। लेकिन वायरस आकार बदलने में माहिर होते हैं ताकि प्रतिरोधक क्षमता को धोखा दे सकें।

टीके शरीर को वायरस की पहचान करने में मदद करते हैं और ऐंटीबॉडीज को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह एक टीका वायरस के एक हिस्से को रोक सकता है। सब-यूनिट टीके वायरस के एक हिस्से को काबू करते हैं। अमूमन फ्लू शॉट्स और हैपेटाइटिस बी में इसका इस्तेमाल होता है। कुछ हल्के किस्म के टीके कमजोर किस्म के जीवित वायरस के खिलाफ कारगर होते हैं। खसरे का टीका इसी तरह का है। इसी तरह कुछ निष्क्रिय टीके भी होते हैं जो मृत वायरस को काबू करते हैं। रैबीज का टीका इसी श्रेणी का है। वर्ष 2017 में दावोस में कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशंस (सीईपीआई) की शुरुआत हुई। यह एक निजी-सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय नॉर्वे में है। सार्स, इबोला और जीका जैसे खतरनाक वायरस के उभार से निपटने के लिए इसका गठन किया गया। इसका मिशन टीके के विकास की गति तेज करना और इसकी पहुंच व्यापक बनाना है। सीईपीआई अब कोविड-19 के खिलाफ नए टीके के विकास के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग कर रहा है। इसमें कुछ दवा कंपनियों के साथ कार्यक्रम और क्वींसलैंड विश्वविद्यालय तथा यूएस नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी ऐंड इनफेक्शस डिजिजेज के साथ शोध कार्यक्रम शामिल है।

सीईपीआई संभावित टीकों को तेजी से क्लीनिकल परीक्षण के लिए भेजेगी। उसका लक्ष्य मात्र 16 सप्ताह में वायरस की जीन सीक्वेंसिंग से लेकर क्लीनिकल परीक्षणों को प्रक्रिया को पूरा करना है। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में शोध इस दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। वहां वैज्ञानिकों के एक दल ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसे मोलेक्यूलर क्लैंपिंग नाम दिया गया है। इसमें किसी वायरस के जीवित नमूने के बजाय आधुनिक आनुवांशिक अनुक्रमण के जरिये सीधे जेनेटिक कोड का अध्ययन किया जाता है।

कोविड-2019 का जीन अनुक्रमण 11 जनवरी को चीन में प्रकाशित हुआ था। क्वींसलैंड की टीम ने 'स्पाइक' के लिए कोड पर जोर दिया। इसे तैयार करने के लिए उन्हें पूरा वायरस बनाने की जरूरत नहीं होगी। 3डी में स्पाइक को मापने के लिए क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया गया था। यह बायोमोलेक्यूल को समझने के लिए ठंडे कक्षों में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए यह नई तकनीक है। इसके लिए 2017 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

इसके पीछे सोच यह है कि एक ऐसा कारगर टीका तैयार किया जाए जो कुंडलीकृत स्पाइक को कोशिकाओं में घुसने और उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले ही पहचान सके। अगर स्पाइक वायरस के मुख्य शरीर से अलग हो जाती है तो यह सीधी हो जाती है और यही वजह है कि इसके कुंडलीकृत आकार को पहचानना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर मोलेक्यूलर क्लैंपिंग काम आता है। यह प्रोटीन के छोटे क्लैंप का इस्तेमाल करके स्पाइक को उसके निर्धारित कुंडलीकृत आकार में रखता है। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसे सात साल पहले विकसित किया था।

पिछले सप्ताह विश्वविद्यालय के एक दल ने घोषणा की कि वह इसकी क्लैंप आकृति का पता लगाने में सफल रहे हैं और एक सप्ताह के भीतर जानवरों पर इसका क्लीनिकल परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। इसके तहत क्लैंप आकृतियों के बड़े जत्थे बनाए जाएंगे और इससे संभावित टीके का निर्माण किया जाएगा। अगर यह प्रयोग जानवरों में सफल रहता है तो फिर इंसानों पर इसका क्लीनिकल परीक्षण किया जाएगा। इन तरीकों से एक सफल टीके का विकास किया जा सकता है। अलबत्ता, सीईपीआई का मानना है कि इंसानों के लिए टीका विकसित होने से पहले इसे करीब 21 परीक्षणों से गुजरना पड़ सकता है। उम्मीद है कि इस संकट से पंजीकरण और नियामकीय मंजूरियों की रफ्तार बढ़ेगी और फिर बड़े पैमाने पर टीकों का उत्पादन शुरू होगा। यदि यह प्रक्रिया काम करती है तो अगली बार कोई नया वायरस आया तो उसके खिलाफ ज्यादा तेजी से कार्रवाई हो सकती है।

कानाफूसी

अमेरिकी राष्ट्रपति और बाजार

वर्ष 2000 से अमेरिका के राष्ट्रपति लगभग हरेक पांच वर्षों के अंतराल पर भारत यात्रा पर आते रहे हैं। वर्ष 2015 में बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर विशेष अतिथि थे। ठीक पांच वर्षों के बाद डॉनल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए। इससे पहले नवंबर 2010 में भी ओबामा भारत आए थे। दिलचस्प बात है इन दोनों अवसरों पर शेयर बाजार लगभग उच्चतम स्तर पर था। ट्रंप की यात्रा के समय भी बाजार का रुख कुछ ऐसा ही है। सोमवार को 800 अंक की गिरावट झेलने के बाद भी बाजार जनवरी में पहुंचे शीर्ष स्तर के इर्द-गिर्द है। एक ब्रोकर ने कहा, 'जब ओबामा आए थे तो सेंसेक्स 20 हजार पर था। वह दूसरी बार आए तो सूचकांक 30 हजार तक पहुंचा था। इस समय बाजार करीब 40 हजार से ऊपर है। अब यह उम्मीद करें कि अगली बार जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आएंगे तो सेंसेक्स 50 हजार पार निकल गया होगा।'

ट्रंप नहीं छाछ!

अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आयोजित 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन समारोह के साक्षी रहे लोगों को कुछ बातें रास नहीं आईं। भाषा की दिक्कत (ट्रंप का भाषण) और अहमदाबाद की गर्मी ने उनके उत्साह पर पानी फेर दिया। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भाषण शुरू भी नहीं किया था कि कई लोग वहां से जाते दिखाई दिए। कुछ लोग, जो धूप से ज्यादा ही परेशान लग रहे थे, उन्होंने समारोह स्थल पर बांटी जा रही छाछ से अपना गला तर किया। अब छाछ बांटने वाले काउंटरों पर भीड़ राहत पाने के लिए जमा हुई थी या समारोह स्थल छोड़ने का बहाना ढूंढने गई थी, इस बारे में तो केवल कयास लगाए जा सकते हैं।

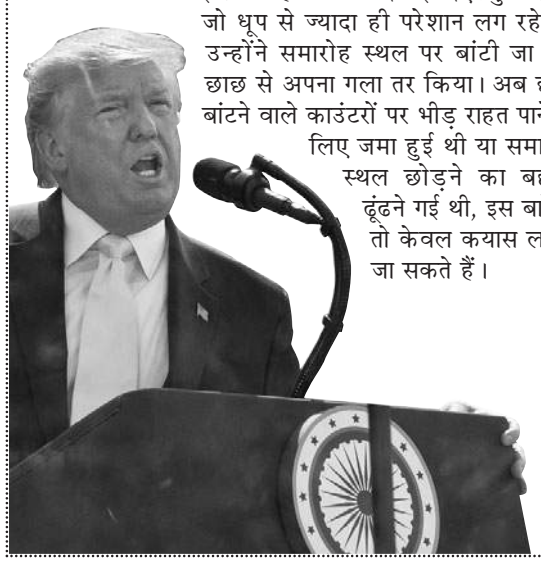

आपका पक्ष

वायरस से संकट तो किसी को अवसर

संकट किसी के लिए समस्या हो सकती है तो किसी के लिए यह अवसर के रूप में सामने आता है। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोनावायरस के कारण जहां चीन के साथ कई देश समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं यह कई देशों को एक नया अवसर प्रदान कर गया है। वायरस के बचने के लिए चेहरे पर लगाने वाले मास्क की बिक्री अचानक बढ़ गई है और जहां तक अनुमान है कि उत्पादन से अधिक मांग बढ़ गई है तथा ये अधिक कीमत पर भी बिक रहे हैं। वहीं चीन जिन उत्पादों का दूसरे देशों को निर्यात करता था अब वे देश चीन से आयात करने से बच रहे हैं। ऐसे में वे देश चीन को छोड़कर अन्य देशों से उत्पादों का आयात करने लगे हैं। भारत से वस्त्र, खाद्य उत्पाद के निर्यात की मांग उन देशों से बढ़ी है जो पहले चीन से आयात करते थे। ऐसे में कोरोनावायरस चीन के लिए संकट लाया है लेकिन यह

दक्षिण कोरिया के सोल में कोरोनावायरस से बचने के लिए लोग मास्क लगा रहे हैं

भारत तथा अन्य देशों को एक नया अवसर प्रदान भी किया है। अगर पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो इंडोनेशिया अपने यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भारी छूट प्रदान कर रहा है। थाईलैंड में भी पर्यटकों की संख्या कम हो गई है जहां पहले कुल पर्यटकों में से एक तिहाई चीनी पर्यटक होते थे। अब चीनी पर्यटकों की संख्या में कमी आने से थाईलैंड के पर्यटन उद्योग में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि वायरस से लड़ने के लिए विश्व के सभी देशों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि यह वायरस अगर आज चीन में तबाही मचा रहा है तो कल यह दूसरे देशों में भी फैल सकता है तथा चीन जैसे हालात पैदा कर सकता है। बहरहाल भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए तथा जहां तक हो सके चीन की मदद भी करनी चाहिए। चीन भले ही भारत का प्रतिस्पर्धी देश है लेकिन पड़ोसी होने का फर्ज भारत को निभाना चाहिए। वक्त पर एक एक पड़ोसी ही पहले काम आता है। ऐसे में भारत को चिकित्सीय मदद के साथ-साथ अन्य सामान भी चीन भेजने चाहिए।

प्रियंका तिवारी, नई दिल्ली

कल्याणकारी सरकार को जनादेश

भाजपा जीत के प्रति अतिआत्मविश्वास में रही और उसने केजरीवाल पर प्रहार करते हुए उन्हें आतंकवादी तक कहा, जो दिल्ली की जनता के गले नहीं उतरा। अनुच्छेद 370 और सीएए के खिलाफ आंदोलनों की धुंध ने भाजपा की छवि को भी धूमिल किया। जनता के बीच संदेश यह गया कि दिल्ली को राहत आप पार्टी ही पहुंचाएगी, न कि भाजपा। अपने विगत कार्यकाल में आप पार्टी ने खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार किए। दिल्ली में मुफ्त और सस्ती बिजली-पानी की सुविधा ने निम्न और मध्य आय वर्ग को भारी राहत प्रदान की है, जो आप के फिर से चयन का प्रमुख कारण रहा। दिल्ली चुनाव के नतीजे केंद्र और व दूसरे राज्यों की सरकारों के लिए अनुकरणीय इस रूप में भी है कि मुफ्त सुविधाएं जनता को देने के बाद भी सरकार घाटे में नहीं है। आय और शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ ही जनता ने जातिवाद और संप्रदायवाद से परे आपको जिताकर कल्याणकारी सरकार चुनने का संदेश प्रसारित कर दिया है।

प्रदीप माथुर, अलवर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

सोना गिरा, लेकिन दूर रहे खरीदार

चीन और शेष दुनिया में कोरोनावायरस के प्रसार से सोने की चमक बढ़ी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 25 फरवरी

वैश्विक रुझान के बाद मंगलवार को सुबह के कारोबार में सोने की कीमत में 0.5 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। सोने जैसी सुरक्षित समझी जाने वाली धातु में नुकसान से बचने के लिए इक्विटी में बड़ी बिकवाली की आशंका के बीच निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली की गई। शुरुआती कारोबार में सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अप्रैल की डिलिवरी के लिए वायदा कारोबार में 1,200 रुपये तक गिरकर 42,371 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। जवेरी बाजार में सोने के दाम 1,000 रुपये तक गिरकर 42,406 रुपये पर रह गए। हालांकि सोना बाद में 778 रुपये या 1.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 42,637 रुपये पर बंद हुआ। इसी तरह चांदी का भाव 980 रुपये या 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 48,055 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।

सोने की कीमत में गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस धातु के लिए रुझान पर केंद्रित रही। लंदन के हाजिर कारोबार में सोने का भाव 1,659 डॉलर प्रति औंस पर खुला और शुरुआती कारोबार में यह चढ़कर 1,664.04 डॉलर पर पहुंच गया। लेकिन मुनाफावसूली की वजह से यह दिन के निचले स्तर 1,633.13 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। लंदन में दोपहर के शुरुआती कारोबार में सोना थोड़ा सुधरकर 1652.80 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था।

कल्याण ज्वैलर्स के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक टी एस कल्याणरमण ने कहा, 'मंगलवार को आभूषण मांग काफी कमजोर रही। हालांकि सोने की कीमत सोमवार के ऊंचे स्तर से थोड़ी नीचे रही, लेकिन ग्राहकों का उत्साह देखने को नहीं मिला।'

- जवेरी बाजार में सोने के दाम मंगलवार को 1,000 रुपये तक गिरकर 42,406 रुपये पर रह गए
- एमसीएक्स पर अप्रैल डिलिवरी के लिए 1,200 रुपये तक गिरकर 42,371 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा
- चांदी का भाव 980 रुपये या 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 48,055 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ

अंतरराष्ट्रीय बाजार में 25 फरवरी को कीमत

समय	डॉलर/औंस	समय	डॉलर/औंस
00.00 (रात)	1,672	9.30	1,657
0.30	1,672	10.00	1,655
1.00	1,657	10.30	1,655
1.30	1,655	11.00	1,654
2.00	1,658	11.30	1,649
2.30	1,660	12.00 (दोपहर)	1,637
3.00	1,660	12.30	1,638
3.30	1,659	13.00	1,642
4.10	1,659	13.30	1,642
4.30	1,658	14.00	1,646
5.00	1,658	14.30	1,652
5.30	1,653	15.00	1,652
6.00 (सुबह)	1,648	15.30	1,651
6.30	1,648	16.00	1,656
7.00	1,649	16.30	1,653
7.30	1,655	17.00 (शाम)	1,645
8.00	1,656	17.30	1,646
8.30	1,658	18.00	1,650
9.00	1,658	18.30	1,651

भारतीय समयानुसार, स्रोत- ब्लूमबर्ग, संकलन- बीएस रिसर्च

कल्याण ज्वैलर्स ने पिछले सप्ताहांत के दौरान स्थिर बिक्री दर्ज की है। कल्याणरमण ने कहा, 'शादी का सीजन और अक्षय तृतीया का समय नजदीक आने से हमसे कीमतों के बारे में ज्यादा पूछताछ की जा रही है और ग्राहक अभी से ही सोने की खरीदारी की बुकिंग करा रहे हैं।'

सोने की कीमतें पिछले आठ महीनों में तेजी से चढ़ी हैं और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता की वजह से निवेशकों ने लगभग 30 प्रतिशत का शानदार प्रतिफल कमाया है। जापान और चीन जैसे देशों द्वारा मौद्रिक प्रोत्साहन की घोषणा की गई है और कई अन्य देश भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मंदी से बचाने के लिए अरबों डॉलर के प्रोत्साहन की योजना बना रहे हैं। वहीं निवेशक सुरक्षित समझी जाने वाली परिसंपत्तियों पर जोर दे रहे हैं। चीन और शेष दुनिया में कोरोनावायरस के प्रसार से भी सोने की चमक मजबूत हुई है, क्योंकि खराब आर्थिक परिवेश में सोना पसंदीदा निवेश विकल्प बन गया है। बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड के शोध प्रमुख विशाल वाघ ने कहा, 'सोना मौजूदा समय में तेजी के चरण से गुजर रहा है, जो सात-आठ वर्षों में एक बार आता है, जिसमें यह धातु लगभग 30-40 प्रतिशत चढ़ी है। सोने में तेजी को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से मदद मिली है। सोने में आज आई गिरावट निवेशकों द्वारा महज एक अस्थायी मुनाफावसूली थी, जो कुछ समय तक बरकरार रहेगी।'

मंगलवार को सोने की कीमतें अस्थिर बनी रहीं। अप्रैल डिलिवरी के लिए सोना मंगलवार को एमसीएक्स पर 43,176 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर खुला, जो पिछले दिन के 43,580 रुपये के बंद स्तर की तुलना में बड़ी गिरावट थी। अप्रैल स्वर्ण अनुबंध के भाव में पिछले दिन के बंद स्तर से 1.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

पिछले अनुमान से बेहतर होगा चीनी उत्पादन

इस्मा ने उत्पादन अनुमान बढ़ाया, सितंबर तक चीनी का स्टॉक 1 करोड़ टन था

राजेश भयानी
मुंबई, 25 फरवरी

चीनी उत्पादक कंपनियों की संस्था भारतीय चीनी मिल संगठन (इस्मा) ने अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के सीजन के लिए अपना चीनी उत्पादन अनुमान बढ़ा दिया है। जनवरी 2020 के आखिरी सप्ताह में गन्ना क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिये किए गए अध्ययन के आधार पर इस्मा ने आज अपनी बैठक में कहा कि चीनी उत्पादन 2.65 करोड़ टन रहेगा।

गन्ने की कटाई और शेष क्षेत्र की इन सैटेलाइट तस्वीरों से अब तक गन्ने की पैदावार का संकेत मिला है। साथ ही इससे चीनी सीजन की शेष अवधि में गन्ने की संभावित पैदावार का भी संकेत मिला है। इस्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है, 'इस अनुमान पर सहमति बनी थी कि 2019-20 के दौरान चीनी उत्पादन नवंबर 2019 में इस्मा द्वारा जताए गए 2.6 करोड़ टन के अनुमान की तुलना में थोड़ा सुधरकर 2.65 करोड़ टन पर रहेगा।'

बी श्रेणी के शीरे और गन्ने के रस के जरिये एथनॉल के ज्यादा उत्पादन की वजह से चीनी में कमी को ध्यान में रखे जाने के बाद यह अनुमान व्यक्त किया गया है।

उत्तर प्रदेश में मिलों द्वारा लगभग 1.19 करोड़ टन का उत्पादन किए जाने की संभावना है, जो पूर्ववर्ती वर्ष के लगभग समान है। बड़ी गिरावट महाराष्ट्र में दिखेगी, जहां उत्पादन लगभग 62 लाख टन पर अनुमानित है, जबकि 2018-19 में वहां 1.072 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था। तीसरे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य कर्नाटक में लगभग 33 लाख टन उत्पादन का अनुमान है जबकि 2018-19 के चीनी सत्र में यह 44.3 लाख टन पर था।

- इस्मा का चीनी उत्पादन 2.65 करोड़ टन रहने का अनुमान
- उत्तर प्रदेश में मिलों द्वारा लगभग 1.19 करोड़ टन का उत्पादन की संभावना
- महाराष्ट्र में 62 लाख टन का अनुमान जबकि 2018-19 में 1.072 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था
- कर्नाटक में 33 लाख टन उत्पादन का अनुमान है जबकि 2018-19 के चीनी सत्र में यह 44.3 लाख टन पर

इस्मा ने अनुमान जताया है कि इस सीजन में चीनी निर्यात 50 लाख टन पर रहेगा और सोमवार को मिलों के लिए निर्धारित कोटे को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि वे तय कोटे के तहत निर्यात में विफल रही हैं। हालांकि इसे कुल निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के लिहाज से एक अच्छी पहल के तौर पर देखा गया है, क्योंकि यह कोटा उन मिलों को पुन: आवंटित किया गया जो अपने कोटा का इस्तेमाल करने में सक्षम रही हैं।

इस्मा ने कहा है, '2019-120 में एथनॉल आपूर्ति के लिए अभिरुचि पत्र के अनुसार, 2019-20 के दौरान बी श्रेणी के शीरे और गन्ने के रस से तैयार एथनॉल की आपूर्ति के लिए अनुबंध 61.63 करोड़ लीटर और 10.6 करोड़ लीटर है। अन्य निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उम्मीद है कि कुछ और एथनॉल आपूर्ति को अनुबंधित किया जाएगा जिसमें बी श्रेणी के शीरे और गन्ना रस से तैयार एथनॉल भी शामिल है।'

चीनी मिलों पर 2,400 करोड़ रुपये बकाया

भाषा
नई दिल्ली, 25 फरवरी

चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का पिछले दो चीनी सत्रों का 2,400 करोड़ रुपये का बकाया है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। लगातार दो चीनी सत्रों 2017-18 और 2018-19 में अधिशेष चीनी उत्पादन की वजह से चीनी की कीमतों में गिरावट का रुख है। इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति प्रभावित हुई है।

अधिकारी ने बताया कि पिछले महीने तक चीनी मिलों ने 2018-19 (अक्टूबर-सितंबर) के चीनी सत्र का 84,700 करोड़ रुपये और 2017-18 का 84,900 करोड़ रुपये चुकाया था। अभी चीनी मिलों पर 2018-19 के चीनी सत्र का 2,300 करोड़ रुपये और 2017-18 का 100 करोड़ रुपये का बकाया है। अधिकारी ने कहा कि गन्ना किसानों को भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। अधिकारी ने कहा कि अभी तक विभिन्न सहायता योजनाओं के तहत चीनी मिलों को 1,574 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

चीनी निर्यात का समय बढ़ा

केंद्र सरकार ने मंगलवार को चीनी मिलों के लिए, वर्ष 2018-19 के अंतिम सत्र के दौरान आवंटित चीनी कोटे के निर्यात करने की समय सीमा 14 मार्च तक बढ़ा दी है। खाद्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। वर्ष 2018-19 की शेष चीनी कोटे का निर्यात करने की अंतिम समय सीमा 15 फरवरी को समाप्त हो गई। सरकार ने मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार लाने और गन्ने का बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2018-19 सत्र (अक्टूबर-सितंबर) के लिए न्यूनतम संकेतक निर्यात कोटा के तहत 50 टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग 38 लाख टन चीनी पहले ही निर्यात की जा चुकी है। *भाषा*

और बढ़ी सामरिक साझेदारी

वैश्विक सामरिक साझेदारी में भारत और अमेरिका ने बढ़ाए तेज कदम

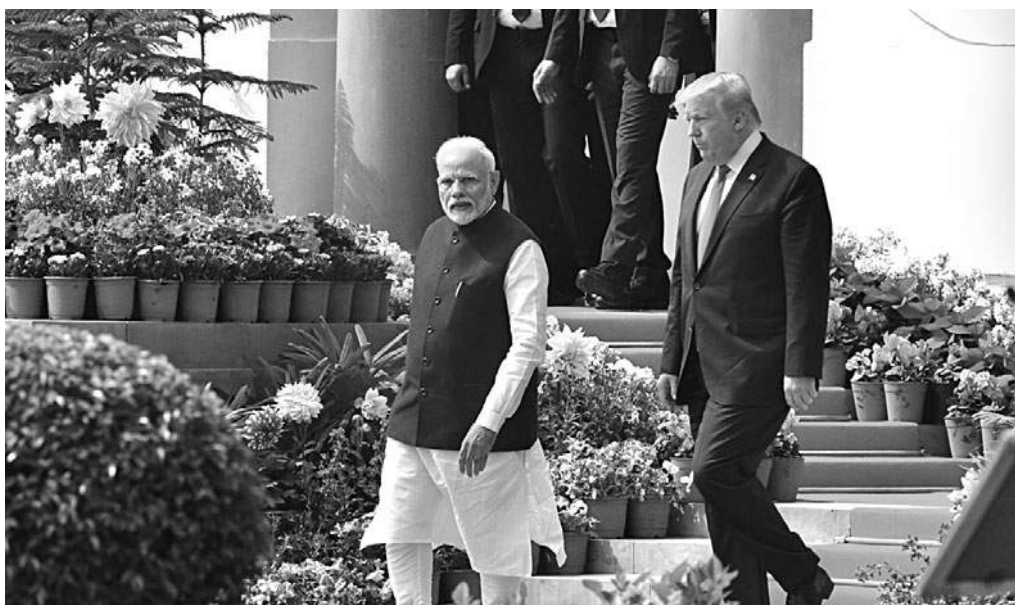

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉनल्ड ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच हुए 300 करोड़ डॉलर के रक्षा सौदे

अजय शुक्ला

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की दो दिवसीय भारत यात्रा दोनों देशों के बीच सामरिक तथा रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। हालांकि कारोबार या परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों पर गतिरोध को खत्म करने वाले करार नहीं हो पाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 'आज राष्ट्रपति ट्रंप और मैंने हमारी साझेदारी को व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला लिया है।' मोदी और ट्रंप ने क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव (क्वाड) को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। यह हिंद-प्रशांत रणनीतिक तानेबाने का एक अहम हिस्सा बन सकता है। यह उन लोकतांत्रिक देशों को एक साथ ला रहा है, जो चीन के उभार से चिंतित हैं।

ट्रंप ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी और मैं अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की क्वाड पहल में नई जान डाल रहे हैं। मेरे कार्यभार संभालने के बाद हमने पहली क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक की। मेरा अनुमान है कि आप इसे बैठक कहेंगे, लेकिन यह उससे बहुत अधिक है। इसके तहत आतंक निरोधी, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है ताकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त खुला रखा जा सके।'

बीते 15 वर्षों के दौरान भारत क्वाड और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना के साथ सैन्य अभ्यास करके चीन से दूर रहा है। मोदी ने कहा, 'बीते कुछ वर्षों के दौरान हमारी सेनाओं के बीच सहयोग में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है।'

ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की कि भारत की सेना ने सैन्य हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के साथ करार किए हैं। ट्रंप ने कहा, 'आज हमने अपना रक्षा सहयोग बढ़ाया है। इसमें भारत तीन अरब डॉलर की राशि में अपाचे और एमएच-60 रोमियो हेलिकॉप्टरों समेत आधुनिक अमेरिकी सैन्य उपकरण खरीदेगा, जो दुनिया में सबसे बेहतर हैं। इन सौदों से हमारी संयुक्त रक्षा क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी क्योंकि हमारी सेनाएं लगातार कंधे से कंधा मिलाकर सैन्य अभ्यास कर रही हैं।'

ट्रंप को अमेरिका के साथ भारत का 24 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष खटकता है। हालांकि इन सौदों से भारत की अमेरिका के रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़कर 20 से 21 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगी। अमेरिका की विनिर्माता कंपनी बोइंग के मुताबिक भारतीय सेना को दुश्मन पर हमला करने वाले अपाचे हेलिकॉप्टर अपने एएच-64ई कॉन्फिगरेशन में मिलेंगे, जिनकी आपूर्ति 2023 से शुरू होगी।

यह अपाचे हेलिकॉप्टर का नया संस्करण है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने 2011 में करना शुरू किया था। बोइंग का कहना है कि उसके पास 26 नई उन्नत तकनीक हैं, जिनमें ज्यादा शक्तिशाली इंजन, कंपोजिट रोटर ब्लेड और मानव रहित हवाई यानों को नियंत्रित करने की क्षमता आदि शामिल है।

दुनियाभर में 2,400 अपाचे हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें से 400 से अधिक ताजा एच-64ई मॉडल के हैं। भारतीय वायु सेना पहले ही 22 अपाचे एच-64ई खरीद चुकी है, जो मई तक देश में पहुंचेंगे। सेना ने अब छह अपाचे हेलिकॉप्टर खरीदे हैं, लेकिन ये एक स्ट्राइक कॉर्प्स की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भविष्य में और अपाचे खरीदे जाने के आसार हैं। हैदराबाद स्थित कंपनी टाटा बोइंग एयरोस्पेस लिमिटेड (टीबीएएल) पहले ही दुनियाभर के बहुत से अपाचे ऑपरेटर्स के लिए हेलिकॉप्टर फ्यूजलिज का विनिर्माण करती है। टीबीएएल टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और बोइंग का संयुक्त उद्यम है।

मोदी ने कहा कि भारत में ऐसे विनिर्माताओं की संख्या बढ़ रही है, जो वैश्विक वेंडरों के लिए उन्नत रक्षा और अंतरिक्ष कलपुर्जों का विनिर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और प्लेटफॉर्म में सहयोग से भारत की रक्षा क्षमताओं में इजाफा होगा। हमारे रक्षा विनिर्माता एक-दूसरे की आपूर्ति शृंखलाओं का हिस्सा बन रहे हैं।'

भारत में अमेरिका के हथियारों की खरीद बढ़ रही है और भारतीय विनिर्माता वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़ रहे हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि उनके बीच तकनीक साझा करने के क्षेत्र में संबंध मजबूत नहीं हो रहे हैं, जो भारत चाहता है। इसमें उपकरणों की डिजाइन और विकास साथ मिलकर करना है ताकि भारतीय कंपनियां को इनके विनिर्माण की जानकारी प्राप्त हो सके और वे यह जान सकें कि क्यों स्वदेशी हथियार विकसित करने की जरूरत है।

भारत के एक रक्षा विज्ञानी ने कहा, 'भारत और अमेरिका ने रक्षा तकनीक एवं व्यापार पहल (डीटीटीआई' शुरू की थी, लेकिन इससे एक भी सफल परियोजना सामने नहीं आई है।'

ट्रंप-मोदी की बैठक में महत्त्वाकांक्षी डीटीटीआई परियोजना- भारत के दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विशाल की डिजाइन में अमेरिकी सहायता के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत का रक्षा बजट स्थिर बना हुआ है, इसलिए वह ऐसी परियोजनाओं में मामूली वित्तीय सहायता दे सकता है।

रिश्तों में गर्मजोशी का आगाज

1. हैदराबाद हाउस में संवाददाताओं से बातचीत करते ट्रंप और मोदी
2. ट्रंप से गले लगते मोदी
3. हैप्पीनेस क्लास से मेलानिया हुईं प्रभावित
4. ट्रंप की बेटी इवांका अपने पति के साथ
5. दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में मिलानिया का स्वागत करते बच्चे
6. महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते डॉनल्ड ट्रंप
7. राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी और नरेंद्र मोदी के साथ मिलानिया और ट्रंप
8. हैदराबाद हाउस में ट्रंप उनकी पत्नी मिलानिया और प्रधानमंत्री मोदी

फोटोः संजय शर्मा और पीटीआई

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से सवाल करते रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी

नियमों को उदार बनाने के लिए ट्रंप की सराहना

श्रेया जय

अमेरिका में कारोबारी महौल में सुधार के लिए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने नियमन के अंकुश को कम करने की घोषणा की है जिसकी देश के उद्योग जगत के दिग्गज तारीफ कर रहे हैं। करीब एक दर्जन उद्योगपतियों ने ट्रंप से एक उच्चस्तरीय राउंडटेबल में मुलाकात की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बैठक के दौरान अपने कार्यकाल की उपलब्धियों और दोबारा चुने जाने पर भी चर्चा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक और चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि वह अमेरिका में 7 अरब डॉलर का निवेश करना चाहते हैं। अंबानी ने कहा, 'रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र ऐसी भारतीय कंपनी हैं जो चीनी कलपुर्जे का इस्तेमाल नहीं करती है।' इस पर ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा, 'आपका मतलब हुआवेई से है?'

मई 2019 में ट्रंप ने हुआवेई को काली सूची में डालने का आदेश देते हुए कहा कि यह चीनी सरकार के भेदिये के तौर पर सहयोग दे रही है। अमेरिका ने कंपनी को अपने देश की आपूर्ति शृंखला से मदद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसकी जरूरत उत्पाद बनाने के होती थी। अंबानी ने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व ने भारत को भी कर राहत देने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा, 'भारत ने अमेरिका के मॉडल का अनुसरण किया है और पहली बार आयकर में कटौती की गई है।'

इस बैठक में करीब एक दर्जन शीर्ष उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया जिनमें आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला, टाटा समूह के एन चंद्रशेखरन, ओयो होटल्स के रितेश अग्रवाल, भारत फोर्ज के प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी, लार्सन ऐंड टुब्रो के चेयरमैन ए एम नाइक और बायोकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार शॉ आदि शामिल थीं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण एजेंडा है। अंबानी और कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि त्वरित मंजूरी की वजह से अधिग्रहण और कारोबारी सौदे बेहद आसान हो गए हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, 'ऐसा तभी तक है जब तक मैं इस पद पर हूं। अगर मेरी जगह कोई दूसरा आता है तब यह सब कुछ थम जाएगा। हमने इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती की है और नियमन को काफी उदार बनाया है। इसी वजह से आप सब अमेरिका में निवेश कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में बाजार में 70-80-90 फीसदी तक की तेजी दिखी है। ट्रंप ने कहा, 'अगर मैं जीत जाता हूं तब बाजार में हजारों-हजार अंक की तेजी आएगी।'

कर कटौती का ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इस वजह से सुधार हो रहा है क्योंकि उपभोक्ताओं के हाथों में खर्च करने लायक काफी पैसे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, 'अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करने की वजह से यह है कि हमारे उपभोक्ता अब अमीर हैं जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। हमने इसके लिए काफी काम किया है मसलन रोजगार सृजन के मौके तैयार करने के साथ ही कर कटौती भी की है।' स्टील क्षेत्र का प्रतिनिधित्व टाटा समूह कर रहा था जिस पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर वह दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं चुने जाते हैं तब अमेरिका में एल्युमीनियम और स्टील कारोबार लगभग खत्म हो जाएगा। कारोबारी समुदाय के लिए नियमों में ढील दिए जाने की बात को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने कहा कि छूट के कई चरण अभी पाइपलाइन में हैं। ट्रंप ने कहा कि कुछ नियमनों को सांविधिक प्रक्रिया से हटाया जाना है लेकिन उनकी सरकार कानून की संख्या में कमी लाने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने चीन के साथ एक करार किया है और चीन अब अमेरिका में एक साल में 250 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है।

अमेरिका को साझेदारी से ज्यादा फायदा: गोयल

नेहा अलावधी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका काफी तेजी से एक बड़ा व्यापारिक सौदा कर सकते हैं। गोयल ने कहा, 'मैं इस बात से खुश हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में औपचारिक तौर पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। मेरे विचार से अमेरिका को इस साझेदारी से ज्यादा फायदा मिलेगा।' उनका कहना है कि यह पहले के मुक्त व्यापार समझौते से अलग होगा जो दशकों तक चला करते थे। मोदी और ट्रंप ने मंगलवार को विभिन्न मुद्दों मसलन व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर प्रमुख प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की थी। गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और अमेरिका-भारत कारोबार परिषद (यूएसआईबीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इन दोनों उद्योग संस्थाओं ने '500 अरब डॉलर के रोडमैप: अमेरिका-भारत द्विपक्षीय साझेदारी' से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया, 'भारत और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते का घरेलू उद्योगों पर व्यापक असर दिखेगा और इसके एक स्पष्ट लागत-मुनाफा विश्लेषण से ही हम कुल असर का अंदाजा लगा पाएंगे।' इस रिपोर्ट में उद्योग के साथ एक व्यापक स्तर पर सलाह-मशविरा करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है ताकि सबसे बेहतर कदम का मूल्यांकन किया जा सके।

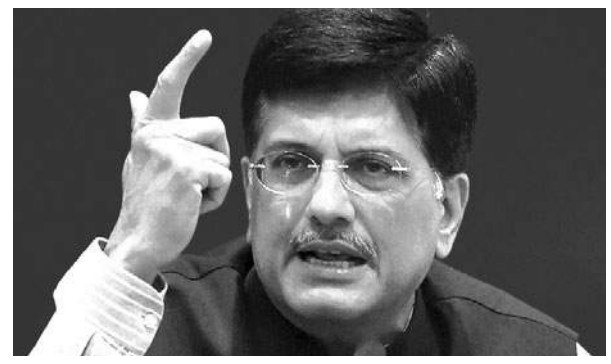

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही है बातचीत

उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इस मुक्त व्यापार समझौते में भी समान तरह से हिस्सेदारों से मशविरा लिया जाएगा जैसा कि पिछले साल भी विभिन्न उद्योग समूहों, अलग-अलग हितधारक समूहों आदि के साथ भी चर्चा की गई थी। इनसे सेवाओं को खोलने, निवेश प्रोटोकॉल, पारस्परिक हितों के क्षेत्र पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के उद्योग प्रतिनिधियों और हितधारकों को जोड़ने की पहल की जा सकती है। गोयल ने कहा, 'मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि जो कुछ भी किया जाएगा वह दोनों देशों के हित में होगा।' उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इसकी पहले दौर की वार्ता कर चुके हैं और उसे अंतिम रूप भी दे चुके हैं।

उन्होंने कहा, 'हम कानूनी रूप से इस पर विचार करेंगे और इसे जल्द पूरा करेंगे।' गोयल से एक व्यक्ति ने भारत में विदेशी निवेशकों का रुझान सकारात्मक नहीं होने के बारे में पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि लोगों का भारत में निवेश करने के लिए स्वागत है, लेकिन हमारे गर्व की कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं मानता हूं कि कोई व्यक्ति किसी देश में धर्मार्थ के लिए निवेश करता है। कोई भी व्यक्ति किसी देश में अपने मौकों के लिए निवेश करता है और भारत ये मौके मुहैया कराता है।'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीएए को बताया भारत का आंतरिक मामला

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) समेत विवादास्पद मुद्दों से बचते हुए कहा कि यह भारत को देखना है और उम्मीद है कि वह अपनी जनता के लिए सही फैसले ले रहा है। अपनी भारत यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समग्र वार्ता के बाद ट्रंप ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने मोदी के साथ धार्मिक आजादी के विषय पर विस्तार से चर्चा की।

ट्रंप ने कहा, 'हमने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की। मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री बेमिसाल हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि वह चाहते हैं कि लोगों को धार्मिक आजादी मिले। उन्होंने मुझे बताया कि भारत में उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बहुत मेहनत की है। अगर हम पीछे की ओर देखें और अन्य स्थानों पर क्या हो रहा है, उसकी अपेक्षा देखें तो उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता पर वाकई बहुत काम किया है।'

राष्ट्रीय राजधानी में अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के समय हिंसा की घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने केवल इतना कहा, 'जहां तक अलग अलग हमलों की बात है तो मैंने इनके बारे में सुना, लेकिन मैंने उनसे उस बारे में बात नहीं की। यह भारत का मामला है।' सीएए के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह इस बारे में बातचीत करना नहीं चाहेंगे। उन्होंने कहा, 'उम्मीद है कि वे अपनी जनता के लिए सही फैसले ले रहे हैं। यह वाकई भारत का मामला है।'

नई दिल्ली के जाफराबाद में सीएए समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़पों के बाद सुरक्षा बल फ्लैग मार्च निकालते हुए : पीटीआई

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बताया कि वह मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बहुत करीब से काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मोदी से तालिबान के साथ अपने देश के शांति समझौते के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत इसे होते देखना चाहेगा। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए फिर एक बार मध्यस्थता की पेशकश की और कहा कि उनके दोनों देशों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। *भाषा*

पृष्ठ 1 का शेष

कश्मीर पर मध्यस्थता की फिर की पेशकश

कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी समस्या बताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर लंबे समय से बहुत से लोगों के लिए समस्या रहा है और हर कहानी के दो पहलू होते हैं। उन्होंने तनाव कम करन के लिए दोनों देशों के बीच फिर से मध्यस्थता की पेशकश की।

ट्रंप ने वार्ता के दौरान पाकिस्तान का मुद्दा सामने आने का जिक्र किया और कहा, 'अगर मैं मध्यस्थता करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं करूंगा।' उन्होंने कहा, 'मेरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ भी अच्छे समीकरण हैं, वे सीमा पार आतंकवाद को काबू करने के लिए काम कर रहे हैं।'

राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाता सम्मेलन में मोदी को एक शानदार नेता और भारत को एक अद्भुत देश बताया। उन्होंने कहा, 'हमने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि भारत में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिले। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कड़ी मेहनत की है।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत बहुत सारे सैन्य हार्डवेयर खरीद रहा है और ऊर्जा क्षेत्र में भारत-अमेरिकी सहयोग बढ़ रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या रूस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, ट्रंप ने कहा कि खुफिया एजेंसियों ने उनके साथ कभी ऐसी कोई सूचना साझा नहीं की।

ट्रंप ने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद पर काबू पाने के बारे में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जितना मैंने किया उससे ज्यादा किसी ने किया है। ट्रंप ने कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद से निपटने पर कहा कि रूस, सीरिया और ईरान को ऐसा करना चाहिए।